

ग्रसाचारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग I--- सण्ड 1

PART I—Section 1

प्रापिकार से प्रकासित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 74]

मई बिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 1971/क्योव्ठ 7, 1893

No. 741

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 1971/JYAISTHA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पूष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रका जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

# बजट 1971-72 वित्त मन्त्री का भाषण

28 मई, 1971

महोदय,

इस वर्ष 24 मार्च को मैंने सम्मान्य सदन के सम्मुख 1971-72 का श्रन्तरिम अजट पेश किया था। उस समय मैंने सम्मान्य सदस्यों को यह श्राश्वासन दिया था कि वर्तमान सब में प्रस्तुत किये जाने वाले मुख्य बजट में, श्रन्तरिम बजट में की गई व्यवस्था की श्रपेक्षा विकास श्रीर सामाजिक कल्याण पर परिव्यय में काफी श्रिधिक वृद्धि की जायेगी। इसी वचन क़ो पूरा करने के लिये श्राज मैं श्रापके सामने उपस्थित हुआ हूं --

### मिंग स्थित

- 2. इसी सप्ताह, सरकार ने 1970-71 की 'म्रायिक समीक्षा' इस सम्मान्य सदन के पटल पर प्रस्तूत की थी। इस समीक्षा से यह पता चलता है कि सामान्य रूप में अर्थ व्यवस्था की स्थिति वस्तुतः माणाजनक है मौर हाल के पिछते वधीं की मनेक्षा भव वह भावी कार्यों को निपटाने के लिये अधिक क्षमता रखती है। हम एक बार फिर 1970-71 में भी उस लक्ष्यको प्राप्त कर सके हैं जो हमने चर्त्य ग्रायोजना में प्रार्थिक विकास की समग्र दर के सम्बन्ध में निर्धारित किया था। कृषि के क्षेत्र में बराबर प्रगति हो रही है, प्रत्न का उत्पादन बहुत ही संतोषजनक दर से बराबर बढता रहा है। श्रीद्योगिक क्षेत्र में, कुछ ग्रत्यावश्यक कच्ची सामग्रियों की कभी के कारण कुछ उद्योगों के उत्पादन सें थोड़ी रुकावष्ट ग्राई है, ग्रीर कुछ ग्रन्य उद्योगों में ग्रद भी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। परन्तु हमारे आयात- प्रतिस्थापन के कार्यों में कुछ नये क्षेत्र शामिल किये गये हैं भौर सातवें दशक के मध्य में जो मन्दी की स्थिति आई थी \_ वह ग्रब काफी हद तक दुर हो गई है। इसके श्रलावा, लघु उद्योग क्षेत्र में विकास की स्थिति सबसे धिक उत्साहजनक है। भ्रतेक लक्षणों से यह पता चलता है कि यदि एक बार सरकारी निवेगों की मान्ना में पर्याप्त बद्धि हो गई तो फिर सभी उद्योगी में एक साथ प्रगति हो जायेगी। प्रारम में कुछ स्कावटों के बाद, वर्ष के अखिरी महीनों में, निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हई है। तथापि, उद्योग भीर निर्यात बोनों के सबंध में जो एक बड़ा काम करना अब भी बाकी है, वह है, उनके संगठन को बढ़िया बनाना । कच्ची सामग्री की कमी श्रौर प्रक्रियात्मक देरी की समस्याएं तो हैं ही, इनके साथ ही हमें कुछ उद्योगों के संबंध में कार्य-चालन के निम्न स्तर ग्रीर प्रति इकाई ऊंची लागत की समस्याओं का भी सामना करना है। अतः लागत में कभी करना और कार्यकृशलता में सुधार करना ये दोनों ही कार्य, श्रीद्योगिक विकास श्रीर निर्यात के क्षेत्र में नई गतिशीलता लाने के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- 3. कृषि के क्षेत्र में भो, प्रभी हमारे प्रयत्नों में ढ़ील देने का प्रवसर नहीं प्राया है। हमें प्रभी धान की प्रधिक उपज देने वली ऐसी किस्मों की खोज चालू रखती होगी जो देश की कृषि एंय जलवायु सबधी भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में काफी समय तक टिक सकें। सिचाई की सुविधाओं को भी बढ़ाना होगा जिससे कि दोहरी फपलें उगाने के प्रचार-कायकमों को सुनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सके। जशर-वाजरा-वर्गीय प्रताजों के बीजों की कीट -प्रतिरोधी बढ़िया किस्मों की हमारी खोज भी जारी रहनी चाहिये। दालों ग्रीर कपास, तेलहन ग्रीर जूट समेत वाणिज्यिक फपलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी जिस्मेदारी है। 1970-71 में, ग्रनाज की कीमतों में पर्याप्त स्थिरता रही, हालांकि उनमें कभी-कभी कुछ गिराबट भी ग्राई। यदि किसानो के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कीमतों को गिरने से रोकने का प्रयत्न नहीं करती तो वास्तव में ग्रनाज की कीमतें बहुत गिर जातीं। इतना होने के बाबजर भी सामान्य मूल्य स्तर में कुल मिला कर वृद्धि ही हुई जिसका मुख्य कारण यह या कि वाणिज्यिक फपलें कम उपलब्ध हुई। ऐसी स्थिति में हम मूल्यों को स्थिर रखते हुंए ग्रगने विकास की गित को तब तक तीव्र नहीं कर सकते जब तक कि वाणिज्यिक फपलों के उत्पादन में वृद्धि नहीं की जाती।
- 4. बाह्य वित्त के क्षेत्र में, हालांकि हम प्रश्तरिष्ट्रीय मुा निधि के प्रीप्राते बहाया दायित्वों को पूरा करने का श्रेय ले सकते हैं, फिर भी हमारे शोशन-रोध की स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं रही है जितनी कि वह 1969-70 के प्रंत में थी। निर्यात में उन्नेखातीय सुधार हुआ है। साथ ही श्रीधोगिक गतिविधियों में वृद्धि होते रहने से, ग्रायात की मात्रा

में भी वृद्धि हुई है। बकाया श्रायात लाइसें नों ने पना चनना है कि चानू वर्ष के दौरान श्रायात में ख्रीर भी ृद्धि होगी। इस्पात, कराम, तेल श्रीर तेलहन की कमी के कारण, हमें प्रारम्भ में की गई कल्पना से काफी श्रिधिक मात्रा में श्रायात करने की योजना बनानी पड़ेगी। पिछने वर्ष के दौरान नई सहायता के श्रावंटन में भी कमी हुई है श्रीर ऋग परिशोधन का भार भी बड़ना ही गया है। फनतः श्रायात की वित्त व्यवस्था के लिये उननध्य महायना की शुद्ध (नेट) राशि धट गई है। श्रतः हम श्रयने शोधन — रोज के बुद्धिमतापूण प्रवन्ध के मामने में थोड़ी सी भी दिनाई लहीं बरत सकते।

# नीतियों का पुननिर्वारण

- 5. इस सरकार को तीन महीने पहने जाना से जो मारी आदेश मिला था वह आदेश नना जशाद के लिये और अधिक मामाजिक न्याय के साथ-पाय ती अ आधिक विकास के लिये था। इसमें संदेह नहीं कि सामाजिक न्याय का श्रीगगेण प्रत्येक व्यक्ति के लिये रोजगार और काम-जन्ते के अवसरों को वहाकर ही किया जा सकना है। पिछने वर्ष के दौरान, शहरी बेरोजगार व्यक्तियों और ग्रामीण अन्य-रोजगार-प्राप्त व्यक्तियों के लिये लाभनद रोजगार पैदा करने के उग्रय करने की दशा में बहुन कुछ किया जा चुका है। राष्ट्रीय हमने बेंकों ने गत वर्ष अपने कायों में काफी विस्तार किया जिनका उद्देश्य अब तक उनिक्षा क्षेत्रों के लिये और प्रान्ता रोजगार चालू करने वाले व्यक्तियों के लिये अधिक ऋग को व्यवस्था करना था, वे भिवज्य में और अधिक विस्तार करना चाहने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दान करने के लिये एक जोरदार कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है और मोटे नौर पर सरकार का उद्देश्य यह है कि देश के सभी भागों में प्रत्येक परिवार के कन-से—कम एक व्यक्ति को रोजगार अवश्य मिने। साथ ही, सरकार का यह संकल्प है कि रोजगार पैदा करने वाली ये योजनाएं केवन तक्ष्य उनायों के का में नहीं बल्क उनसे देहानों में नई सड़ कीं, भूमि सुवार, भूमि विकास, जन-मल निकासी व्यवस्था आदि के का में प्रतिरिक्त भीतिक परिमन्ति का भी निर्माण हो।
- 6. सम्मान्य सदस्यों को यह भी स्मरग होगा कि गन वर्ष देहातों में, विशेष हो से छांटे किसानों के लिये थ्रौर पिछड़े क्षेत्रों में, ोजनार के अवसरों में वृद्धि करने के लिये विशेष निर्माण —कार्यक्षम चालू किये गये थे। ये योजनाएं आगे भी चालू रहें । इनके अनावा, जैना कि मैं अभी बनाऊंगा, हम शिक्षित बेरोजगारों को, राष्ट्र को सेवा करने के रचनात्मक अवसर खोज निकालने के काय में सश्यना देने क लिये बजट में एक विशेष व्यवस्था करने का प्रस्ताव करते हैं।
- 7. रोजपार में सबसे अधिक वृद्धि तो तभी हो सकती है जबिक सब ओर आर्थिक गितिविधियों की रफ्तर को तेज कर दिया जाए। आत: यह अतिवार्थ है कि आ बोजना के अन्तर्भंत कथ्य को ऊने स्तरीं पर ही जारी रबा जाए और किनी प्रकार की कभी न होने दो जार। सब यह है कि इन विषय में हमारे 1970-71 के काम को देखों हुर तो अभी हमारे लिये बहुत- कुछ करना बाकी है। हलांकि में गतवप्र को अभिन्ना इस वर्ष आयोजना पिर्ध्यिय में प्यस्ति वृद्धि करने का प्रस्ताय कर रहा हू, फिर भो अधिक जोर इन बात पर ही देना होगा कि जिन आयो- जनागत प्रायोजनाओं के लिये बजट में व्यवस्था की जा रही है उनका कार्यान्वयन समग्र पर हो।

- 8. पहले से तीज गित से विकास करने और पहले से अधिक सामाजिक ग्याय प्रदान करने के सक्ष्य तज तक मृग-मरीचिका ही सिद्ध होगे जब तक कि उनके लिये सापेक्षिक मूल्यों की स्थिरता का वातावरण तैयार नहीं किया जाएगा। हम बढ़ते हुए मूल्यों के पूंजी --निवेश और प्राय-वितरण पर पड़ने वांले प्रतिकूल प्रभावों को बिलकुल नजरांदाज नहीं कर सकते। मुद्रा-स्फीति के कारण, उत्पादन की कुशलता को बढ़ाने और इकाई लागत को कम करने के प्रयत्न भी निष्फल हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स लिये लगातार सतर्क रहने की प्रावश्यकता है। इस प्रकार, तीवतर गित से विकास करने के प्रभियान में, मूल्यों में स्थिरता लाने का समानास्तर लक्ष्य भी समन्वित है। इस काय में सफलता प्राप्त करने के लिये हमें। मुद्रा शक्तियों के प्रभाव की भी जांच बराबर करते रहना होगा।
- 9. वार्षिक भायोजनाएं बनाने की हमारी प्रिक्रिया का स्वरूप ही ऐसा है कि इस प्रिक्रिया में ही भायोजनागत प्राथमिकताओं भीर उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण कर लिया जाता है। ऐसी घड़ी में, जबकि हमें हाज ही में एक नया भाषेण मिला है, यह भी भावध्यक हो गया है कि समग्र भायोजना का एक बार फिर भाकसन कर लिया जाये। भव से ऐसे उपायों पर भिक्ष जार दिया जाएगा जिनसे प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन की गति तेज हो, रोजगार के भवसरों का विस्तार हो भीर प्रावेशिक भ्रममानताओं सहित सभी भ्रममानताओं में कभी हो। सम्मान्य सदस्यों को विदित ही है कि भ्रायोजनागत सहायता के भावंटन भीर ऐसे ही राजस्व सम्बन्धी भीर भन्य उपायों से, विकास को, जिसमें पिछड़े इलाकों में भी थीन गिक विकास शामिल है, बढ़ावा देने के लिए हाल के दर्षों में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। विदेशी सहायता के माध्यम से प्राप्त मुद्रा सहित हमारे विदेशी मुद्रा के साधनों का भावंटन करते हुए भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा। पिछड़े इलाकों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं पर, भायोजना बनाते समय ही, उचित ध्यान देना होगा जिससे कि भायोजना के भ्रतगंत भारतिक श्रौर विदेशी साधनों के भ वटन में देश के विकास भ गो को, भ प दिशेष रूप से प्रश्रित स्व प्रत्येत का उचित हिस्सा मिल सके।
- 10. हमारे सरकारी क्षेत्र के उद्देमों ने प्रर्थव्यवस्था के ग्रौधोगिक ग्राधार को गहरा ग्रौर विस्तृत कर दिया है ग्रौर वे कुछ मूलभूत सामाजिक उद्देश प्राप्त करने में सफल हुए है। इन उद्दमों का कुशक्ततापूर्ण कार्य-निष्पादन सरकार के समग्र विकास-प्रयत्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी उद्यम जितनी योग्यता के साथ ग्रायोजनागत प्रस्तावों को कियान्वित करेंगे, ग्रर्थ-व्यवस्था में भी प्रति वर्ष लगभग उतनी ही उन्नति हो सकेगी। श्रतः जो प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक देरी इन उद्यमों की प्रगति को रोकती है, वह गहरी चिन्ता का विषय है। इसी प्रकार, सरकारी उद्यम क्षेत्र को भी काफी बड़ी मात्रा में ग्रधिशेष (सरप्लस) देना होगा, क्योंकि यह श्रधिशेष भावी विकास का प्रमुख साधन है। पिछले वर्ष के वौरान, सरकारी उद्यमों की सामान्य कुशक्तता को बढ़ाने के लिए ग्रनेक कदम उठाए गए हैं। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक एकक में तालिकागत वस्तुग्रों ग्रौर संयंत्र तथा मशीनों के उचित अनुरक्षण के लिए ग्रौर कार्मिक प्रबंध तथा ग्रौद्योगिक संबंधों की समस्या को सुलझाने के लिए ग्रिधकार-धिक व्यान दिया जा रहा है। जहां तक ग्रौद्योगिक संबंधों की समस्या को सुलझाने का सम्बन्ध है, हम श्रीमक संयों से सलाह ग्रौर परामर्श ग्रवश्य लेना चाहेंगे। सरकारी क्षेत्र की कार्य-कुशक्तता में उनका हित भी समानरूप से निहित है। मुझे ग्राशा है कि उनके सहयोग से हमारे सरकारी उद्यमों में भौद्योगिक सम्बन्धों के एक नये कम का सुत्रपात हो सकेगा।

- 11. वाणिजियक वैंकों में से बहुत में कैन प्रव सरकारी-क्षेत्र का ही भाग हैं। यहां भी, मैं कैं को कार्य कुरातता में मुदार करते के लिए, श्रमिक संगों के नेताओं का सहयोग चाहूंगा। प्रभी हाल हो में इस विजय में गुरूपात हो बुकी है जबकि मैंने कैंकों के कर्न वारी भोर प्रवंधक वर्ग से बातचीत को थी। उस समय हमते ऋण देने को योजना बनाने और जमा को रकमें जुटाने आदि के विषय में चर्चा को थी। मैं इस पद्धति को आगे भी चालू रखता चाहता हूं। नए निदेशक मंडलों के बारे में भी अही बीयणा को जाने वालो है; उनमें क्वाट कर्म वारियों (अवार्ड स्टाफ) और अधिकारियों के प्रतिनिधि भी सम्मिलत होंगे; मुझे आशा है कि ये नए निदेशक मडल बैंकों को प्रक्रियाओं और नीतियों में सुधार करने के कार्य को अमीष्ट दिल्ला में आगे बढ़ाएंगे।
- 12. प्रत्येक राष्ट्रीय कृत बैंक को एक वार्षिक ऋण श्रायोजना बनाने के लिए कहा गया है जिससे यह मुनिष्चित हो सके कि विभिन्न क्षेत्रों को श्रीर विशेष रूप से श्रव तक उपेक्षित क्षेत्रों को विए गए ऋण उनकी श्रावश्यकताश्रों के श्रनुरूप हैं श्रीर ने मुद्रा-विस्तार के प्रतिमानों (नार्म) के श्रनुसार भी है। श्रात्मित्योजन को प्रोत्माहन देने के हेतु ऋण योजनाश्रों का मुझाब देने के लिए भारतीय रिजर्थ बैंक द्वारा नियुक्त की गई समिति ने श्रनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं; वाणिष्यिक बैंकों द्वारा इन सुझावों को मूर्न हि विया जा रहा है। एक श्रन्य समिति को, छोटे ऋणकर्ताश्रों श्रीर जनता के कमजोर वर्गों को सहायना देने के उद्देश्य से भिन्न-भिन्न ब्याज-दरों की योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था; उसने श्रमो-श्रमो श्रयनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पहली श्रप्रैन को एक ऋण प्रत्यामृति (गारंटी) निगम की स्थाना की गई है, इसका काम छोटे ऋण-कर्नाश्रों को बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की गारंटी देना है। सम्मान्य सदस्यों को यह भी मालूम है कि सरकार ने श्रमो हाल हो में, मरकारो वित्तीय संस्थान्श्रों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को सामान्य गेयरों में बदलने के लिए मार्गवर्गक सिद्धान्त निश्चित कर दिए हैं। इन मार्गवर्गक सिद्धान्तों से एक सयुक्त क्षेत्र, जिसको हम पर्याप्त महत्व देते हैं, की स्थापना करने में काफी सहायता मिलेगी।
- 13. मुझे विश्वास है कि सम्मान्य सदस्य देश में ग्राम बीमा के कारबार की ग्राने हाथ में ले लेने के सरकारी निर्णात से प्रसन्न हुए हैं। यह निर्णय उस प्रक्रिया का एक चरम बिन्दु है जो उस समय प्रारंभ की गई यो जबकि हमने इस्नीरियल बैंक ग्रॉफ इंडिया और जीवन बीमा कारबार का राष्ट्रीयकरण किया था, ग्रीर जिस प्रक्रिया को, हमने दो वर्ष से कम समय पहले बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके, तेज गिन प्रदान की थी। इन उपायों के फनस्वरूप, वितीय संस्थाओं द्वारा जनता से जुटाई गई गा। की समस्त राशि ग्रव वस्तुनः राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के ग्रनुसार काम में लाई जा सकेगी।

# संतोधित अनुमान 1970-71

- 14. श्रन्तरिम बजट में, मैंने संकेत दिया था कि 1970-71 के श्रन्त में कुल मिलाकर 230 करोड़ रुगये का घाटा रहेगा। जो बजट प्रलेब में श्राज प्रस्तुत कर रहा हूं, उतमें श्रन्तरिम बजट में दिए गए 1970-71 के सरोधित श्रनुमान दोहराए गए हैं, क्योंकि श्रधिकतर मामलों में वास्तविक श्रांकड़े श्रमी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, नशीनतम संकेतों के श्रनुमार, 1970-71 का समग्र घाटा, मसे ढर है, 270 करोड़ रुपये का हो मकता है।
- 15. मन्तरिम बजर पेश करते हुए, मैंने इस बात पर चिता व्यक्त की थी कि स्रतेक राज्य भारतीय रिजर्व वैंक में, प्रश्ने बाते में जना से स्रधिक रकमें ले रहे हैं। मुने यह कहते हुए खेद होता है कि 1970-71 के दौरान राज्यों को 195 करोड़ हनये की विशेष सहायता देने के बावजूद भी राज्यों

द्वारा रिजर्ष बैक से श्रोवर ड्रापट लेने की प्रश्निया में कोई कमी नहीं बाई है। यह तथ्य इस स्थिति से स्पष्ट होता है कि गत मार्च मास के श्रंत में कम से कम 14 राष्यों ने बुल मिलाकर 260 वरोड़ रुपये के श्रोवरड़ापट ले रखे थे। राष्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता, जिस्का उद्देश्य राष्यों को एक कि श्रायोजना-परिव्यय के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद देना है, श्राने वाले वर्षों में उत्तरोत्तर कम हे ती चलि जाएगी। इस संदर्भ में, श्रोवरङ्गापटों की समस्या श्रीधक गंभीर हो गई है। मैं राष्यों से यह शनुरोध करूंगा कि वे श्रातिरक्त साधन जुटाने के लिए श्रीधक से श्रीधक प्रयत्न करे श्रीर श्रायोजना-भिन्न व्यय की खहोतरी पर कहे से कड़ा नियंदाण रखें।

## बजट घनुमान, 1971-72

16. सम्मान्य सदस्यों को याद होगा कि अन्तरिम बजट में मैंने 1971-72 की किन्द्रीय आयोजना के लिए 1,195 करोड़ रुपये अर्थात् 1970-71 के बजट में की गई व्यवस्था के अराअर कि ही व्यवस्था की थी। उस समय मैंने कहा था कि चालू धर्ष की केन्द्रीय आयोजना के लिए व्यवस्था में, आवश्यकताओं और साधनों की समीक्षा करने के बाद, बुद्धि की जाएगी। मैं केन्द्रीय आयोजना के परिव्यय में 155 करोड़ रुपये की बुद्धि करके उसे 1,350 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार इस वर्ष, 1970-71 के वास्तिक व्यय के संभावित स्तर को तुलना में, 300 करोड़ रुपये से अधिक बुद्धि होगी। जिन अधिक महत्वपूर्ण कों को लिए अन्तिम बजट की अरेक्षा अब काफी अधिक बजटव्य-वस्था की जा रही है उन में से कुछ है—नीवहन (16 करोड़ रुपये), पनन (13 वरो रुपये), सड़के (10 करोड़ रुपये), खान और खनिज (9 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य और पिचार-नियोजन (12 करोड़ रुपये), जाक-तार (11 करोड़ रुपये), कृषि (32 वरोड़ रुपये) और अक्र-बसूली (18 करोड़ रुपये)। मैंने राज्यों और संघीय राज्य कोंन्नो की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में अंतरिम बजट में पहले से ही 785 वरोड़ रुपये की पूरी व्यवस्था वर दी थी; इसके मुकाट ले 1970-71 के बजट में 711 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी।

17. श्रायोजना-परिव्यय में वृद्धि करने से भी सम्भवतः श्रल्प प्रश्विधि में रोजगार के प्रवसरों की तस्काल व्यवस्था नहीं हो सकेगी। श्रतः मैंने सरकारी क्षेत्र के पिर्व्यय में कुछ श्रौर वृद्धि करने का निश्चय किया है जिससे श्रितिरवत रोजगार के प्रवसर भी पैदा होगे श्रौर जनता के कमजोर वर्गों को भी राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के जोरदार कार्यक्रम के लिए मार्च बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी परन्तु हमारे शिक्षित युवकों श्रौर युवतियों में भी बरोजगारी की समस्या उतनी ही विकट है। हमारा दृढ़ संकत्प है कि हम उन्हें कुंठाग्रस्त होकर भटकने नहीं देंगे। हम सिक्रयरूप से उनकी सहायता करने का प्रस्ताव करते है ताकि वे प्रपने ग्रापको लाभप्रद श्रौर रचनात्मक काम-धन्धों में लगा सकें। जिनसे देश की श्राधिक प्रगति की रपतार भी पहले से श्रधिक तेज हो सकेगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम इंजीनियरों श्रौर तकनीशियनों समेत शिक्षित बेरोजगार व्यव्तियों के लिए विशंष रूप से बनाई गई योजनाश्रों के लिये इस बजट में, जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हू, 25 करोड़ रुपये की श्रौर राशि निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। योजना श्रायोग और संग्रिध मंत्रालयों से परामर्ग करके इन योजनाश्रों के व्यौरे तैयार किये जा रहे है।

18. सम्मान्य सदस्यां को यह जानकर प्रसन्तता होगी कि बच्चों के पोषण के कार्यक्रम के लिए अन्तरिम बजट में जो 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी उसे बढ़ाकर श्रव 10 करोड़ रुपये किया जा रहा है भीर उसे श्रव श्रायोजना में शामिल किया जा रहा है भिश्व कोई संदेह नही है कि इस प्रकार पहले से बढ़ी राशि को व्यवस्था करके भी निर्धन बच्चों के कस्याण श्रीर उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा

उसमें सुधार करने के कार्य की हम शुरूआत ही कर रहे हैं। मुझे यह भी आशा है कि हम इस विषय में आगे आने वाले वर्षों में कुछ अधिक ठोस कार्य करने की स्थिति में होगे। मैं यहां यह भी बतलाना चाहूंगा कि हम पब्लिक स्कूलों में नए दाखिला में से 25 प्रतिशत स्थान गुणवान् उम्मीवारों के लिए सुरक्षित करने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे गुणवान् छान्नों को सरकारी छान्न-वृत्तियां थी जाएंगी।

- 19. गंदी बस्तियों का सुधार करने ने लिए गत वर्ष जो विशेष व्यवस्था की गई थी उसे इस वर्ष भी किया जा रहा है। कलकत्ता महानगरीय विकास प्राधिकरण का कार्य तेजी के साथ काल रखा जाएगा। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि ग्रन्य महानगरीय क्षेत्रों ग्रौर कस्बों में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन की वशा को सुधारने के लिए इसी प्रकार के जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे, सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यदि राज्य सरकारें ग्रौर नगरपालिकाएं इस प्रयोग्जन के लिए सक्षम योजनाएं प्रस्तुत करेंगी तो हम उनके लिए वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे।
- 21. प्रवर्म जपसंहार के रूप में बजट का समग्र चित्र प्रस्तुत करूंगा जो कि प्रायोजना-परिक्यय में वृद्धि करने, रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता देने के लिए क्यवस्था करने, श्रौर मार्च में सन्तरिम बजट पेश किए जाने के बाद क्यय की ग्रायोजना-भिन्न मदों में कुछ श्रनिवार्य वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप श्रंकित हुश्रा है। निष्कान्त व्यक्तियों की राहत के लिए व्यवस्था करने के श्रनाशा मैं विशेष रूप से उस वृद्धि का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि श्रन्न के लिए दी जाने वाली राजसहायता (मित्नडी) के क्यय में हुई है। व्यय की यह रकम 30 करोड़ रुपये रखी गई है जब कि श्रन्तरिम बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है थी। इस समय हिसाब लगाने से मंभव है कि 1971-72 में राजस्व-प्राप्ति 3562 करोड़ रुपये होगी। राजस्व से पूरा किया जाने वाला व्यय 3587 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार राजस्व श्रधिषेप की राशि जो श्रन्तरिम बजट में 114 करोड़ रुपये विखाई गई थी सब 25 करोड़ रुपये के घाटे में बदल जाएगी। पूंजी खाते में ग्राशा है कि विभिन्न श्रन्य बचत योजनाओं के श्रन्तर्गत संग्रहीत राशि श्रव 180 करोड़ रुपये होगी जब कि श्रन्तरिम बजट में वह 155 करोड़ रुपये दिखाई गई थी किन्तु राज्यों को दिए जाने वाले श्रष्टणों की राशि में भी तदनुरूप 16 करोड़ रुपये दिखाई गई थी किन्तु राज्यों को दिए जाने वाले श्रष्टणों की राशि में भी तदनुरूप 16 करोड़ रुपये दिखाई गई थी किन्तु राज्यों को दिए जाने वाले श्रष्टणों की राशि में भी तदनुरूप 16 करोड़

क्ष्मये की वृद्धि हो जाएगी इसलिए इस शीर्ष के झन्तर्गत वस्तुतः 9 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। विने यह भी माना है कि पी॰ एल॰ 480 की प्राप्तियों के झन्तर्गत 40 करोड़ रुपये की झितरिक्त राशि जमा हो जाएगी जो अधिकतर 1970-71 की बची रकम के रूप में होगी। ऋणों और अप्रिमों तथा विभिन्न ऋण जमा शीर्षकों के झन्तर्गत लेन-देन की राशियों सहित कुल पूंजीगत प्राप्ति प्रब 2024 इरोड़ रुपये झांकी गई है और ऋणों और अप्रिमों महित कुल पूंजीगत व्यय 2396 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। अतः पूंजीगत बजट में 372 करोड़ रुपये का घाटा होगा इसके मुकाबले अंतरिम बजट में 354 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था। राजस्व और पूंजीगत खातों को एक साथ रखने के बाद श्रव कुल मिलाकर बजट में 397 करोड़ रुपये की कमी रहेगी। यह झनुमान लगाते समय रेलों के यात्री-भाड़े और वस्तु-भाड़े की दरों में कुछ दिन पहले घोषित परिवर्तनों के केन्द्रीय बजट पर पड़ने वाले प्रभाव को और डाक-तार की मुक्क-दरों में किए जाने वाले उन परिवर्तनों के प्रभाव को भी जिनके बारे में शभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा हिसाब में शामिल कर लिया गया है।

- 22. मुझे यकीन है कि सम्मान्य सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि मैं बजट में इतने बड़े घाटे को पूरा करने के लिए कोई उपाय न कछ। अतः मैं आपसे अनुग्रह की अपेक्षा करते हुए अब उस विषय पर आता हूं जिसके लिए मुझे विश्वास है भाप महानुभाव प्रतीक्षा कर रहे होंगे, यह विषय है—इस घाटे को कम करके अधिक सहाय स्तर तक नीचे ले आने के प्रस्ताव।
- 23. जनता पर नए-नए कर लगाकर प्रतिरिक्त साधन जुटाने का काम विश्त मन्त्री की ऐसी जिम्मेदारी है जिसके लिए शायद ही कोई ईर्ष्या करता हो। फिर भी यदि मुझे इस सदन के सम्मुख प्रति-रिक्त साधन जुटाने के लिए प्रस्ताव पेण करने पड़ रहे हैं तो वे इसीलिए कि मैं उस परिस्थित से बाध्य हूं जिसमें प्रायोजना परिव्यय में वृद्धि करने की प्रायभ्यकता है, श्रतिरिक्त रोजगार के श्रवसर उपलब्ध करने हैं श्रीर पूर्व बंगाल के निष्कान्त व्यक्तियों को मदद देनी है।

# सामान्य सिद्धान्त

- 24. इन प्रस्तावों की रूपरेखा बनाते हुए मैंने कुछ स्थूल सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास किया है। ये सिद्धान्त हैं:--
  - (क) करों के ढांचे को इस रूप में सरल श्रीर युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए कि कर-दाता श्रीर कर-संग्राहक दोनों के लिए कर-निर्धारण का बोझ श्रीर कर से बच निकलने के श्रवसर कम से कम हो आएं;
  - ख) करों का बोझ कुल मिलाकर जनता के विभिन्न वर्गी में इस प्रकार बांटा जाए कि उसकी कियान्विति से भ्राधिक शक्ति के संचय को काफी हद तक कम किया जा सके भ्रीर भ्राय तथा धन की भ्रसमानताएं भी कम हों; श्रीर
  - (ग) नए कराधान के भार से, जहां तक सम्भव हो, श्रावश्यक वस्तुओं की कीमतों के सामान्य स्तर में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए।
- 25. श्रतः, यह भावश्यक्ष है कि जहां तक सम्भव हो, श्रतिरिक्त कराधान श्रधिकतर प्रत्यक्ष करों के रूप में हो जिनका भार विशेष रूप से सम्भन्न क्यों पर पड़े श्रीर यह प्रतिरिक्त कराधान एसे अप्रत्यक्ष करों के रूप में हो जिनका प्रभाव विलास-वस्तुओं श्रीर विलास-वस्तुओं जैसी सामग्री पर पड़ता हो। जहां तक हम श्रप्रत्यक्ष कराधान के बोझ को उत्तरोक्त वस्तु-समूह तक सीमित रखने में सफल होते हैं, वहां तक हमें समाज में श्राय-वितरण के ढांचे में सुधार करने के श्रपने श्रन्य उद्देश्य में भी श्रांशिक रूप से सफलता मिल जाती है।

#### कर-प्रजासम

- 26. कर-प्रशासन को कड़ा करने श्रीर उसे दोषमुक्त करने के दो पहलू हैं। पहला यह कि ऐसा करने से वर्नमान कर-स्रोतों से ग्रितिरिक्त राशि प्राप्त होती है ग्रीर इस प्रकार हर वर्ष भए कर-साधनों को खोजने की श्रावश्यकता कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि चूकि ग्रामतौर पर सम्पन्न श्रीर धनो लोग हो करों से बचने का प्रयत्न करते हैं श्रीर करों की चोरी करते हैं, इसलिए करों मे बच निकतने के रास्तों को बन्द कर देने मे ग्रीर कर-प्रशासन को कड़ा कर देने से इन सम्पन्न लोगों को बाध्य हो कर श्राम श्रीर परिसम्पत्तियों का पहले में श्रीधक भाग छोड़न। पड़ेगा ग्रीर इस प्रकार हमारी राजण्य नीति के एक प्रमुख उद्देश्य को बढ़ावा मिलेगा।
- 27. सम्पत्ति का न्यून-मून्याकन भी धन-कर, पूंजी श्रीभलाम कर श्रीर स्टाम्य गुल्कों ने बच निकलने का एक साधन है। यह काले धन के परिचालन का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बना दुशा है। इस पद्धति को बहुन-कुछ रोका जा सकता है यदि सरकार को उनने दामों में मम्पत्तिया खरीद लेने की श्राक्ति प्राप्त हो जाए जो कि बिको-विलेखों में दर्ज कीमत के श्रानुरूप हों। तदनुमार, हम इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए जालू सब में शोध्य ही एक विधेयक पेश करने का प्रम्ताव करते हैं। श्राशा है, बेईमान श्रादमी की बात को ज्यों-का-त्यों मानकर उनका लाम उड़ाने को दोष नहीं समझा आएगा।
- 28. प्रणासिनक सुधार भ्रायोग की सिकारिशों के भ्रनुसरण में, बेनामी तौर पर सम्पत्ति धारण करने को निष्त्साहित करने के लिए भी चालू मत्र में एक विधान बनवाने का विचार है। यदि कर-निर्धारण के समय कोई व्यक्ति भ्राय भीर धन करों की श्रदायगी से बचने के लिए किसी सम्पत्ति या उस सम्पत्ति के किसी भ्रंण से होने वाली भ्राय की घोषणा नहीं करेगा तो प्रस्तावित विधान के भ्रन्तगैत उसे किसी न्यायालय में उस सम्पत्ति के बारे में श्रपना दावा करने से रोक दिया जाएगा।
- 29. प्रशासनिक मुझार घायोग की सिकारिणों के घनुसरण में हम धारी यह भी प्रस्ताव करते हैं कि सम्पदा शुक्त की बकाया रक्षमों की वसूल करने का काम राज्य सरकारों से लेकर केन्द्रीय धायन्कर विभाग की सींप दिया जाए। चूकि इस मामले में हम राज्य विधान महलों की सहमति से ही कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए एक विधेयक का मनौदा नैयार करके राज्यों के पास भेजा जाएगा।
- 30. यह प्रस्ताव है कि इमारतों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड में स्थित मूल्यांकन कन्न (वेल्यूएणन सेल) को सबल बनायें, जिससे कि वह अपनी गतिविधियों को बढ़ा सके और धन-कर के निर्धारण के मामलों में मूल्यांकन कार्य को शीध्रता से कर सके। आय-कर का विधीरण करने के लिए, चालू वर्ष से जो नई प्रकि मालागू हुई है उसके अतर्गन, ऐसे अधिकांश मामलों में जिनमें विवाद के विषय सारवान् न हों, संक्षिण्न कर-निर्धारण प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उनमें से थोड़े से मामलों की बाद में नमूने के तौर पर छान मेन की जाएगी। इससे आय-कर अधिकारियों को उन सामलों के लिए अभिताकृत अधिक समय मिल सकेगा जिनने बड़ी माला में राजस्व मिल सकता है।
- 31. उत्पादन-शुल्कों के क्षेत्र में, मैं श्रात्म परिहरण प्रक्रिया योजना (सेल्फ रिमूबल प्रोसीजर स्कीम) की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। वह योजना पिछले बो-तीन वर्षों से चल रही है। प्रस्तावित समिति राजस्व की हानि को कम करने के उपायों के बारे में सुझाव देगी। बास्तविक मूल्य से कम या प्रधिक राशि के बीजक (इनवायस) बनाने के विषयों पर विचार करने के लिए जो श्रध्ययन दल नियुक्त किया गया था उसने बीजक मूल्यों में गड़बड़ करके विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में की जाने वाली हानि को रोकने के लिए श्रीक नुझाव दिए हैं। सरकार इसकी सिकारिकों

को कार्यान्वित करने के लिए शीझ ही दिचार करेगी। ऐसे ही एक प्रयोजन से विदेशी मुद्रा विनियमना अधिनियम की भी त्यापक समिक्षा की जा पहीं है और हम इस अधिनियम के कई उपवधों में सशोधन करने के लिए शीझ ही एक विधेयक पेश करने का विचार करते हैं।

## राज्यों से परासर्ज

- 32. पिछले दर्षों में, हसने गहरी क्षेत्रों में श्रायिक श्राय श्राय का पुछ ही ह थो में के दिसा होने और बदने से रोवने के लिए केन्द्र रहर पर, श्ररेक राजरद-सम्बन्धी कदम एठ.ए थे। विन्तु, देह ती क्षेत्रों में ऐसे ही सुधार करने के सम्बन्ध में सर्विय सम्बन्ध के सर्वैध कि परमाधिक र पर व ला प्रतिकाध लगा हुआ है। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि बुछ वर्तमान ग्रसम दियां चालू ही महेंगी श्रथ्या हम ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई श्रसमानताओं के प्रति श्रपनी श्राखं बन्द कर लेगे। श्रन्त तो स्वा, व र का श्राधार तो श्राय या धन की माला ही होना चाहिए, भले ही वह कृषि से श्रथ्या कृषि भिर्म से तो से प्राप्त हुई हो।
- 33. इसी प्रकार, सेवाझों पर भी कर लगाने की केन्द्र की शिव्द यों पर संवैधानिक पिस माएं लागृ है, चाः ये सेवाए दिलास या अर्ध-दिलास के स्टब्स की ही व्यो न हो। चृथि आर्थिक दिकास के लिए साधन जुटाने की जिग्मेधारी में राज्यों और केन्द्र को हाथ बटाना है इस लिए केन्द्र का यह वर्षात्य धीर धायित्व है कि वह साधन जुटाने के लिए इन ध्रष्ट्रते स्रोतों के बारे में राज्यों को बताए, जहां सर्वध िक उपक्रधों ने स्वयं संघ सरकार को विसी प्रकार का कर लगाने से रोक च्छा है। मेरी इन्छा है कि मैं इस सभी विषयों पर राज्यों के वित्त मित्रयों से स्लाह स्वाविण कर और उनसे लगातार सम्पर्क बनाए रखू साकि इस मामले में एक समन्वित राय ली जा सके।

### प्रत्यक्ष कराधान

34. श्रव मैं प्रत्यक्ष कराधान के बारे में नए प्रस्ताव देश करता हूं। यदि हमें श्रवने समाज में ध्याप्त श्राय की श्रसमानताश्रों की समस्या को हुत झाने के लिए एक प्रमानताश्रों कर रठ ना है तो हम सम्भवतः प्रत्यक्ष कराधान के माध्यम का उत्तरोक्षण श्रधिक उपयोग भरने से नहीं देश स्वते । जो प्रस्ताव मैं कर रहा हूं उनसे श्राल् वर्ष में राजस्व की प्राप्ति सीमित माल्ला में ही होगी। परन्तु बुछ दर्षों के बाद इन प्रस्तावों के सन्तित प्रभाव से पर्याप्त माला में राजस्व किलने लगेगा; इसके भी श्रधिक सार्थक बात यह होगी कि इन प्रस्तावों से त्यय-योग्य श्राय श्रीर धन के वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन श्रा जाएगा।

# (क) आय और यन पर कराधान

35. वैयवित्तक ग्राय पर कराधान के क्षेत्र में, व्यवित्यों ग्रीर हिंदू ग्रविभवत कुटुर को के मार ले में ग्राधिभार (सरचार्ज) की दर 10 प्रतिग्रत से कढ़ कर 15 प्रतिग्रत की जा रही है बगर्से कि कुल ग्राय 15,000 र० प्रतिवर्ष से ग्राधिक हो। एक पूरे वर्ष में, इस प्रस्ताव के पिण ग्रस्वरूप राजकाय में 20 करोड़ रुपये की ग्राति रिक्त प्राप्ति होगी; 1571-72 में लगभग 12 वरोड़ रुपये की प्राप्ति होते. की ग्राभा है।

- 36. मैं इस भवसर का उपयोग पूंजी-श्रिभिलाभों (कैपीटल गेन्स) पर कर बढ़ाने के लिए भी करना चाहता हूं; ये भ्रिभिलाभ अनुपाजित भाय का ही एक प्रकार हैं। निगम-भिन्न करदाताओं की कर-योग्य भाय का हिसाब लगाते समय दीर्घावधिक पूंजी-श्रिभिलाभों में से जो कटौती की जा सकती भी उसे श्रव 45 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत किया जा रहा है, जहां ये श्रिभिलाभ जमीनों भीर इमारतों के सम्बन्ध में हों; श्रीर श्रन्य पूंजी-श्रिभिलाभों के मामले में, इस कटौती को 65 प्रतिशत से भटाकर 50 प्रतिशत किया जा रहा है।
- 37. दीर्घावधिक पूंजी-अभिलाभों पर कर के भार को कम्पनियों के मामले में भी बढ़ाया आएगा। अभीनों और इमारतों से सम्बन्धित अभिलाभों के मामले में कर की दरें 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत की जा रही हैं और अन्य अभिलाभों के मामले में कर की दरें 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की जा रही हैं।
- 38. धन-कर के बारे में मैं जो प्रस्ताव कर रहा हूं वे कुछ प्रधिक सक्त हैं। यदि धन के संकेन्द्रण को काफी हद तक कम करना है तो यह प्रत्यावण्यक है कि धन पर प्रधिक कठोर कर लगाए जाएं। सम्मान्य सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष के बजट में शहरी सम्पत्ति पर प्रतिरिक्त धन-कर की दरों में वृद्धि करके, हमने इस दिशा में बढ़ना शुरू कर दिया था। इस वर्ष, में शुद्ध धन के 15 लाख रु० से ऊपर के सोपानों (स्लैंब) पर कराधान में अत्यधिक वृद्धि करना चाहता हूं। श्रव से इन सोपानों पर एक समान रूप से 8 प्रतिशत की दर लागू होगी जब कि इस समय 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच के शुद्ध धन पर 4 प्रतिशत की दर से थ्रौर 20 लाख रुपये से ऊपर के शुद्ध धन पर 5 प्रतिशत की दर से धन कर लगता है। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि कराधान के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तिगत करदाता के मामले में, धन के पहले 1 लाख रुपयों को शुद्ध धन की श्रेणी में शामिल किया जाए शौर हिन्दू प्रविभक्त कुटुम्ब के मामले में धन के पहले 2 लाख रुपयों को शुद्ध धन की श्रेणी में रखा जाए। इस प्रकार, जब तक शुद्ध धन, व्यक्तियों के मामले में 1 लाख रुपये से प्रधिक श्रीर हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के मामले में 2 लाख रुपये से प्रधिक नही होगा तब तक कोई धन कर नहीं लगेगा; परन्तु यदि एक बार वे कर योग्य सीमा में भ्रा जाएंगे तो फिर वह उनके सारे धन पर लगेगा। किन्तु अनुमोदित वित्तीय निवेशों, मालिक के कब्जे में मौजूद मकानों श्रीर कृषि परिसम्पत्तियों पर इस समय जो छूट मिली हुई है वह श्रागे भी जारी रहेगी।
- 39. घरेलू श्रीर व्यक्तिगत श्राभूषणों के लिए श्रीर प्रारम्भिक पूंजी निर्गम के शेयरों के लिए हस घन कर से जो छूट मिल रही है उसे कर भार को कड़ा करने के उद्देश्य से खत्म किया जा रहा है। वाहनों के मामले में,यह छूट श्रव कुल मिलाकर 25,000 रुपये तक ही सीमित रहेगी। धन कर श्रधिनियम में स समय एक व्यक्ति द्वारा श्रपने पित/श्रपनी पत्नी या श्रवयस्क बच्चों को श्रन्तिग्त परिसम्पितयों को कुल धन में शामिल न करने का जो उपवन्ध है, उसे खत्म किया जा रहा है। व्यक्तियों की पित्मम्पितयों को हिन्दू श्रविभक्त कुटुम्बों की पिरसम्पितयों के रूप में मंबदल लेने के संबन्ध में भी ऐसा ही उपबंध किया जा रहा है। हालांकि यह स्वाभाविक है कि इन सब परिवर्तनों से इस वर्ष तो कोई राजस्व प्राप्त नहीं होगा, परन्तु भविष्य में, धन-कर को प्रभावित करने वाले इन उपायों से प्रतिवर्ष लगभग 14.5 करोड़ रुपये की श्रतिरिक्त श्राय हो सकेगी। इससे भी श्रधिक यह महत्वपूर्ण है कि इनके जिस्ये वस्तुत: ध्यक्तिगत धन की एक उच्चतम सीमा निर्धारित हो जाएगी जो वर्तमान सीमा से काफी नीची होगी।

40. कर-म्रायंचन को कठिन बताने के एक और उगय के रूप में, व्यक्तिकी म्रलग संपत्तिके एक हिन्दू भविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति के रूप में, मंगरियर्तन को दान-कर की सीमा के भन्तर्गत साया नाएगा।

# (ख) कमानियों पर कराधान

- 41. मैं कम्पनियों के कराधान के ढांचे में कई परिवर्तन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। हालांकि पूंजी प्रिमिलाभ पर लागू होने वाली दरों को छोड़कर कम्पनियों की साधारण प्राय पर कराधान की दरें वर्तमान स्तरों पर ही रखी जा रही हैं, परम्तु कम्पनी के लाभों पर अतिकर (सर टैक्स) की दर, पूंजी के 15 प्रतिशत से ऊपर के प्रभार्य लाभों के मामले में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करदी जाएगी।
- 42. मैं महसून करता हूं कि नए पूंजी निवेश के सम्बन्ध में विकास-रिबेट देने की पद्धति का समय पूरा हो चुका है। ग्रनः मैं ग्रावश्यक नोटिस दे रहा हू कि 31 मई, 1974 के बाद प्राप्त किए जाने वाले जहाजों भ्रयवा लगाई जाने वाली मशीनों या संयत्रों को कोई विकास-रिबेट नहीं मिलेगा। राजस्व पर इस प्रस्ताव के जो भी प्रभाव पड़ेंगे काफी ग्रधिक परिमाण में होंगे ग्रीर उनका पता 1974-75 के बाद ही, यानी पांचवीं ग्रायोजना के समय से ही चलेगा। किन्तु मैं ग्रयने ग्रापको भली भांति पुरस्कृत समझूगा यदि इस परिवर्तन की पूर्व-सूचना से चतुर्थ भायोजना के शेष वर्षों में निवेश की गति तीव्र हो जाए।
- 43. इस समय, नए श्रीबोगिक उपक्रमों, जहाजों श्रीर श्रनुमोदित होटलों के मामने में लगाई गई पूंजी के 6 श्रितशत तक के लाभ पांच वर्ष की श्रविध तक कर-मुक्त रहते हैं। चूंकि ऋग पत्र श्रीर दीर्घाविधक उद्यार की राशियां किसी प्रकार जोखनी पूंजी नहीं होतीं श्रीर उनके ब्याज के लिए हर हालत में कटौती की जाती है, इसलिए पूंजी के इस प्रकार के श्रविध तक कर-छुट्टी के उपबन्ध को बढ़ाकर सरकार ने बड़ी उदारता दिखाई थी। श्रव मैं श्रक्ताव करता हू कि कर से छूट देने के प्रयोजनों के लिए पूंजी के 6 प्रतिशत की सीमा का हिसाब लगाते हुए, ऋग-पत्रों श्रीर दीर्घावि का उधार की राशियों को शामिल नहीं किया जाएगा। सी एक उपाय से चालू वर्ष के दौरान राज है. में 10 करोड़ इपये की प्राप्ति होगी; एक पूरे वर्ष की श्रामवनी कोई 14 करोड़ क्यये होगी।
- 44. प्रायमिकता-प्राप्त उद्योगों को इस समय करों में उनके लाभ के 8 प्रतिशत तक की विशेष छूट मिली हुई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विशेष छूट कम करके, लाभों के 5 प्रतिशत तक कर दी जाए। इसके प्रलावा, हमने यह भी निश्चय किया है कि प्रायमिकता-प्राप्त उद्योगों की सूची में से एल्यूमिनियम, मोटर, ट्रक ग्रीर वर्से, सीमेंट ग्रीर रीके क्टरियां, सोडा ऐश, पेट्रो-रसायन ग्रीर ग्राटो-मोबाइल उपकरणों को निकाल कर, इस सूची को छोटा कर दिया जाए। सामान्य ग्राधिक स्थित इस समय ऐसी है कि ग्रव यह ग्रावश्यक नहीं रहा कि इन उद्योगों को ग्रागे भी विशेष सुविधाएं दी जाती रहें जो कि श्रव तक उन्हें दी जाती रही थीं। प्रायमिकता-प्राप्त उद्योगों के सम्बन्ध में इन दो उपायों को करने से ग्रागामी वर्षों में 8 करोड़ रुपये की प्राप्त होनी चाहिए; 1971-72 में इससे खगभग 6 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है।
- 45. विशिष्ट वित्तीय परिमम्मित्तयों में किए गए निवेशों से कुन मिलाकर 3,000 रुपये सक की ग्राय की कटौती करने की जो व्यवस्था गत वर्ष की गई थी, वह अब से केवल व्यक्तियों ग्रौर हिन्दू प्रविभक्त कुटुम्बों पर ही लागू होगी।

- 46. प्राथमिकता प्राप्त उद्योग में लगी हुई ग्रह्मजन-द्यारित भारतीय कंपनी से विदेशी कम्पनियों द्वारा प्राप्त लाभांगों के सम्बन्ध में कर के मामले में जो रियायत दी जाती थी, वह खर्म कर दी जाएगी; विदेशी कम्पनियों को भी ऐसे लाभांगों पर 24 5 प्रतिशत की सामान्य दर से कर देना पड़ेगा।
- 47. मेरा पक्का मत है कि ऊचे बेतनों श्रौर पारिश्रमिको की श्रवायगी को निरुत्साहित करने के लिए भी कराधान पद्धित का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि वेतन श्रौर पारिश्रमिक की ऊंची देरें समतावादी समाज के मान-दड़ों के श्रनुरूप नहीं हैं। श्रत. मैं कम्पनियों के कर्मचारियों के उस पारिश्रमिक की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताय करता हूं जो कि कर-योग्य लाभों का हिसाब लगते समय कुल लाभ राशि में से घटा दिया जाता है। यह उच्चतम सीमा 5,000 रु० प्रति मास निर्धारित की जा रही है। परिलब्धियों (परिक्वजिट्स) के मामले में इस समय जो 1,000 रुपये प्रतिमास की उच्चतम सीमा निर्धारित है, उसे साथ मिलाने से पारिश्रमिक श्रौर परिलब्धियों की कुल मिलाकर उच्चतम सीमा, कराधान के प्रयोजनों के लिए 6,000 रुपये प्रतिमास होगी। इसके प्रतिरिक्त, मैं दौरे के समय कर्मचारियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते की कर-कटौती योग्य सीमाग्रों को भी कम करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

## (ग) विविध रियायतें

- 48. कुछ प्रकिषकर समाचार देने के बाद, धब मुझे कुछ विचकर बातें भी कहनी चाहिए। जो कर्मचारी मोटर साइकिल, स्कूटर या मोपेड रखते हैं उनके मामले मे कर-योग्य धाय का हिसाब लगाते हुए, इस समय 60 र 0 प्रतिमास की मानक कटौती दी जाती है, मैं इसे बढ़ाकर 75 र 0 प्रतिमास करने का प्रस्ताव करता हू, जो कर्मधारी इस प्रकार का कोई वाहन नहीं रखते, उनके मामले मे की जाने वाली मानक कटौती 35 रू० प्रतिमास से बढ़ाकर 50 र 0 प्रतिमास कर दी जाएगी।
- 49. जीवन बीमा, भविष्य निधि प्रशादान प्रादि के माध्यम से वीर्घाविधिक बचतों के सम्बन्ध में की जाने वाली कटौती की राशि में भी काफी परिवर्तन किया जा रहा है। इस समय ऐसी वीर्घाविध बचतों के पहले 5,000 रु० का 60 प्रतिशत श्रौर उसके साथ उनकी शेष राशि का 50 प्रतिशत कर-मुक्त है। भव मैं प्रस्ताव करता हू कि ऐसी बचतों के पहले 1,000 रु० के लिए कटौती की माला शतप्रतिशत हो। धनुमत बचतों के श्रगले 4,000 रु० पर प्रस्तावित कटौती 50 प्रतिशत के हिसाब से होगी श्रौर शेष राशि पर 40 प्रतिशत कटौती की जा सकेगी। कटौती के लिए श्रनुमत बचतों की सीमा को व्यक्तियों के मामल में 15,000 रुपए से बढ़ा कर 20,000 रुपए कर दिया जाएगा
- 50. थाहन भौर वीर्घावधिक अचलो के लिए अनुमत मानक कटौरियों में परिवर्तन करने के के परिणामस्थरूप 6,000 रु०की वार्षिक भ्राय वाला कर्मचारी श्राय-कर से मुक्त रहेगा बणर्ते कि वह कम से कम 400 रु० अनुमोदित रूप से बचाए।
- 51. केवल कम्पनियों को ही उपलब्ध होने वाली, तकनीकी जानकारी और तकनीकी सेवाओं के विकास और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए दी जाने वाली कर-सम्बन्धी रियायते अब से व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों और भागीदारी फर्मों के मामले में भी लागू होगी। इस समय अनुसंधान और विकास के लिए भी कुछ और कर-सम्बन्धी रियायते मिलती है।

श्रभी हाल ही में सरकार ने एक सिमिति नियुक्त की है जो इस विषय में स्थिति की समीक्षा करेगी और कुछ श्रन्य राजस्य सम्बन्धी प्रोत्साहन देने के बारे में सिकारिशों करेगी जो कि श्रीचोगिक श्रनुसद्यान को बढ़ावा देने के लिए दिए जा सकते हैं। सिमिति की सिकारिशों को उचित महस्य दिया जाएगा।

- 52. विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों में किए गए निवेशों से प्राप्त 3,000 र 0 तक की धाय की विशेष कटौती, जो व्यक्तियों ग्रीर हिन्दू प्रविभवत कुटुम्बों को उपलब्ध है, प्रागे से सहकारी सिमितियों के पास उनके सस्वयों द्वारा जमा कराई गई रकमों के ब्याज पर भी दी जा सकेगी। इसके घलावा सहकारी सिमितियों के पास उनके सदस्यों ारा जमा कराई गई रकमों पर इन सिमितियों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज पर, स्त्रोत पर ही कर काटे जाने की व्यवस्था लागू नहीं होगी। सहकारी सिमितियों के शेयरों ग्रीर सदस्यों द्वारा उनके पास जमा कराई गई रकमों को प्रतुमोदित निवेश माना जाएगा जो 1.5 लाख र 0 तक धन-कर से मुक्त है। परन्तु मैं यह प्रस्ताव करता हू कि विवेशाधीन न्यासों (डिसकीशनरी ट्रेस्ट) के मामले में, ऐसे निवेशों पर दी जाने वाली छूट को खत्म कर दिया जाए; इन न्यासों को प्रपने शुद्ध धन पर, 1.5 प्रतिशत की समान दर या व्यक्ति के मामले में लागू होने वाली दर में से जो भी ऊवी हो उस दर से कर देना पड़ता है।
- 53. कुछ छोटी-छोटी श्रोर रियायनें भी दी जा रही हैं जिनके बारे में मैं एक साथ ही बता देना चाहना हू। कर्म वारियों की सहकारी मिनितियों को श्रयका मछ नी-अपनाय श्रोर उसके समवर्गी धंधे करने वाली महकारों मिनितियों को उनकी समदन अपावसायिक श्राय पर कर से मुक्ति मिले है। स्यानीय प्राधिकरणों को श्राने श्रिधिकार क्षेत्र से वाहर के गावों में पानी या बिजली की पूर्ति करने से जो श्राय होती है उस पर भी कर नहीं लगेगा। सहकारी श्रावास मिनिति के जिस सदस्य को उस समिति की गृह निर्माग योजना के श्रन्तर्गन एक मकान या पनैट मिला हो वह सदस्य धन-कर के प्रयोजनों के लिए उस सम्पत्ति का स्वामी समझा जाएगा।
- 54. आवासन और शहरी विकास विता निगम को दस वर्ष की अविधि के लिए उसकी आव पर कर से छूट मिनेगी, जमा बोमा निगम (डिगोजिट इन्श्योरेन्स कारगेरेगन) को कर से जो छूट मिन रही है वह अगो पांच वर्ष तक और मिननी रहेगी।
- 55. इस प्रकार प्रत्यक्ष कराधान के त्रिमित्र प्रस्तावों का प्रसंग यहीं मनाध्त होता है। इस रियायतों की हिसाब में लेने के बाद, प्रत्यक्ष करों के नए उरायों से, 1972-73 से, 57 करोड़ रु0 की शाद्ध प्राप्ति होने का श्रनुमान है। किन्तु 1971-72 में तो सम्मनतः 27 करोड़ रुपय से श्रिष्ठिक प्राप्ति न होगी।

### ग्राग्रहयक्ष कराधान

56. अब मैं श्रवस्थक्ष करों पर श्राता हूं। सीमा-मुल्कों के सम्बन्ध में मेरे प्रस्ताव स्यूल रूप से दो श्रीणयों के श्रन्तर्गत श्राते हैं। पहली श्रेणी के श्रस्तावों का उद्देश्य श्रायात शुक्तों के दर-ढांचे को युक्तिसंगत बनाना है। दूसरी श्रेणी के प्रस्तावों का सम्बन्ध उन कई विदेशों के साथ हुए करारों या ठहरावों से है, जिल्होंने हमें कुछ विशिष्ट वस्तुशों पर श्रायात-शुक्क लगाने के मामले में, टैरिक श्रोर व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार (जनरल एपीमेंट श्रान टैरिक एण्ड ट्रेड) की श्राती से मुक्त करना मान लिया है, ये श्रस्ताव इसी के विशामस्वरूध तैयार किये गये हैं।

## (क) ग्रायात<sup>-</sup>शुस्क

- 57. मैं मानता हू कि आयात शत्कों की दरों का वर्तमान ांचा बहुत ही पेवोश है। 'स्थिति यह है कि इस समय सात प्रकार की मूत्यानुसार शुक्त-दरें प्रचलित हैं --15 प्रतिशत, 27 हैप्रतिशत, 35 प्रतिशत, 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत 60 प्रतिशत स्त्रीर श्रन्त में 100 प्रतिशत । इसे पर्याप्त रूप में सरल बनाने के लिए और वर्तमान अक्षातिया को दूर करने के लिए में प्रस्ताव करता हूं कि आयात शुक्क की केवल चार प्रकार की ही दरें लागू रहें, अर्थात 30 प्रतिगत, 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और सत-प्रतिशत।
- 58. मैं मशीनरी की सभी वस्तुयों को 30 प्रतिशत आयात शुन्क की परिधि में नाने का प्रस्ताव करता हूं। हालांकि इससे—प्रायोजना आयातं की शुन्क-दरों में 2 के प्रतिशत अंगों की सीमान्तिक वृद्धि हो जाएगी, परन्तु सामान्य रूप से मशीनरी के शल्क में 5 प्रतिशत अंगों की कभी हो जाने से छोटे श्रीधोगिक एककों को श्रीर उनकरण बनाने वाले ऐसे एककों को, जो कल-पुर्जी के कुछ हिस्से विदेशों से मंगाते हैं श्रीर उन सभी एककों को जिन्हें फाततू पुर्जी या संतुत्रनकारी उनकरणों के रूप में मशीनरी की छोटी वस्तुयों का श्रायात करने की जरूरत पड़ तो है, राहत मित्रेगी। सभी प्रकार की मशीनरी के लिए दरों को एक-प्रमान कर देने से कर-निर्धारण का काम भी सरल हो जाएगा और मुझे आशा है कि इससे कर-निर्धारण का काम शीव्यता से होगा। खेती करने की मशीनों श्रीर श्रीजारों तथा डेरी श्रीर मुर्गीशलन के उनकरणों आबि पर श्रव 15 प्रतिशत की बजाय 30 प्रतिशत शुक्क लगा करेगा।
- 59. कुळ बुनियादी कच्वी सामग्रियों और श्रतीह धातुओं पर प्रवसे 40 प्रतिसा की एक समान दर से शुल्क लगा करेगा। किन्तु लोहे, इस्पात श्रीर श्रापिटे तांबें पर 30 प्रतिसात की नीची सुन्क दरही लाग होगी।
- 60. प्रस्ताव है कि प्रक्षिकांण वस्तुप्रीं पर शुक्क की 50 प्रतिगत की वर्तनान दर को सनाष्त कर के उसके बदले 60 प्रतिशन की उन्ने दर लागू को जाए। पिछ ने दो वर्गों के दौरान, रनायनों प्रौषधियों, ववाग्रों प्रौर बिजली तथा बिना बिजली के उपकरणों पर शुक्क की दरें बड़ा दी गई हैं। अतः श्रब मैं यह प्रस्ताव करता हू कि ऐसी सभी वस्तुभों को एक साथ उसी शुक्क दर के व्याप्ति क्षेत्र में ले जाया जाए।
- 61. श्रव तक ऐसाथा कि समाज के ब्रांजिक सम्मन्त वर्ण द्वारा काम में लो जाने वाली वस्तुन्नों पर, उदाहरणार्थ मोटर गाड़ियों अदि के कल पुजी ब्रोर में तो पर 100 प्रतिवात की बजाव 60 प्रतिजन की बर से शहक लगा करना था, जाविक वह 100 रितार की बर श्रविकांश आवान-किल उपमोंकता वस्तुन्नों के लिए मानक दर है। यह श्रवंगित श्रव दूर को जा रही है। इसके श्रवाला, लगान बीमा भाड़ा कीमत में वृद्धि श्रीर लाभ के उग्व श्रंग को देवते हुए, लींग पर लागू होने वाली परिमानुनार दर को 18 राए प्रति किलोग्राम से वड़ाकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम कि रा जा रहा है।
- 62. टेरिफ और व्यापार के सामान्य करार (गैंड) के बज़ों से छुड़कारा पाने के यरिणामस्वरूप हम श्रव ऐसी स्थिति में श्रा गए हैं जब कि श्रनेक वस्तुओं पर, जैसे खोती के द्रैक्टरों मिट्टी हटाने वाली मशीनों, कचने ऊन, धाग को छोड़कर स्टेनन रेगे, अनिपटे तांबे, जस्ते श्रीर हले सीसे पर, शुक्क लगाया जा सकता है या वर्तमान शक्त-दरों को बड़ाया जा सकता है।

मैं इस अवसर का उपयोग करना चाहता हूं। आयातित स्टेपल रेशे में लाभ के ऊने भंश को बेखते हुए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस पर 100 प्रतिशत शल्क लगाया आए। अनिपट जस्ते, हले सीसे और कच्चे ऊन पर शुल्क की दर 40 प्रतिशत होगी और ताम्बे पर 30 प्रतिशत। आयातित और देशी ट्रैक्टरों की कीमतों में बहुत श्रिष्ठक श्रंतर होने के कारण, मेंने यह भी निश्चय किया है कि आयातित कृषि-उपयोगी ट्रैक्टरों पर 30 प्रतिशत शुल्क लगा दिया जाए। मिट्टी हटाने बाली मशीनों पर भी यही शुल्क-दर लागू होगी।

63. शायात शुरकों के ढांचे को युक्तिसंगत ज्नाने के प्रभावों को धौर टेरिफ धौर व्यापार के सामान्य करार के बंधनों से खुटकारा पाने के बाद किए जाने वाले समायोजनों धौर उत्पादन-शुरकों में किए जाने वाले उन प्रतिसंतुलनकारी परिवर्तनों के परिजामों की, जिनके बार में मैं धभी बताऊंगा, हिसाब में ले खेने के बाद, हमें वर्ष के शेष भाग में लगभग 54 करोड़ रुपए तक धितिरक्त राजस्व मिल जाना चाहिए।

# (ख) उत्पादम शुल्क

- 64. अब मैं उत्पादन गुरुक सम्बन्धी प्रस्ताय पर आता हूं। चीनी, वस्त्र और तम्बाकू पर विकी-कर के बदले अतिरिवत उत्पादन गुरुक लगाने की योजना को चालू रखने के निर्णय के अनुसार, हम चौथी आयोजना की अवधि के अन्त तक, इन अतिरिवत गुरुकों के समग्र भार को बढ़ा कर, निकासी के मूल्य पर 10.8 प्रतिशत तक करने के लिये बचनबद्ध हैं। चूकि यह लक्ष्य 1973-74 तक प्राप्त करना है, इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि चालू वर्ष में ही बड़े पैमाने पर गुरुआत कर दी जाये। फिलहाल, मैंने अपना ध्यान सिगरेटों और कुछ हद तक कपड़े पर केन्द्रित करने का निश्चय किया है।
- 65. धू अपिन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कदाचित एक समय ऐसा भी श्राता है जब कि वह अपने पुराने और बफादार साथी के प्रित अपनीवफादारी को भूलकर भपने स्वास्थ्य की अधिक चिन्ता करने लगता है। जो लोग इस व्यसन को नहीं छोड़ सकते उनको कम से कम यह संतोष होता है कि वे जिनता अधिक कर देते हैं उतना ही वे सामान्य हित को पूरा करने में सहयोग देते हैं। श्रतः में इस विचार से कि मेरे सिगरेट पीने वाले मित्र की जैसी भी प्रतिक्रिया होगी उससे राष्ट्रीय हित की द्रिट से अवश्य लाभ होगा, एक बार फिर सिगरेटों पर कर बढ़ाने का निर्णय लेने के लिये अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूं। इस समय सिगरेटों पर शुल्क के तीन सोपान हैं, अब मैं उनके बदले पांच सोपान रखने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय सिगरेटों पर शुल्क के तीन सोपान हैं, अब मैं उनके बदले पांच सोपान रखने का प्रस्ताव करता हूं। इन सोपानों पर बुनियादी और श्रतिरिक्त शिक्कों में उचित परिवर्तन करने से, मुझे आशा है, चालू वर्ष में 33.20 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो जायेगी जिसमें से 16.40 करोड़ रुपया, बिकी-कर के बदले लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क के रूप में, राज्यों को देना पड़ेगा। इन प्रस्तावों का असर यह होगा कि सस्ती किस्म की सिगरेटों की कीमतों में वो थोड़ी ही वृद्धि होगी परन्तु अधिक महंगी सिगरेटों की कीमतों में अधिक वृद्धि होगी।

- 66. वस्त्त, घौर विशेष रूप से मोटी (कोर्स) घौर वरमीयानी (मीडियम) किस्मों का कपड़ा एक वृत्तियादी जरून्त की चीज है, उनकी कीमतों में 1970-71 के दौरान ग्रत्यधिक वृद्धि हुई है। ग्रतः ग्रन्य विशेषताग्रों के वावज्द, भी, मैंने यह निण्चय किया है कि इस वर्ष वस्त्त पर सुल्क थोड़ा ही लगाया जाये। इसिलए मैं प्रस्ताव करता हूं कि दरमीयानी 'क' ग्रीर 'ख' किस्मों के सूती कपड़े पर मौजूदा ग्रतिरिक्न उत्पादन गुल्क को 4.8 पैमे प्रति वर्ग मीटर की दर से थोड़ा-मा बढ़ा कर 6 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दिया जाये ग्रीर मोटे कपड़े पर 3.6 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले ग्रतिरिक्त उत्पादन गुल्क को पूर्णांकित करके 4 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दिया जाये। परन्तु बहुत बढ़िया (सुपर फाइन) श्रीर बढ़िया (फाइन) किस्म के कपड़े के मामले में तो मैं भौर भी ग्रधिग वृद्धि करना चाहता हूं ग्रीर बहुत बढ़िया श्रीर बढ़िया कपड़े पर लगने वाले ग्रतिरिक्त उत्पादन-गुल्क की दरों को बढ़ा कर कमण: 25 पैसे ग्रीर 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव करता हूं। इन ग्रनेक उपायों से 4.9 करोड़ रुपये का ग्रतिरिक्त राजस्व मिलना चाहिये जो पूरा-का-पूरा राज्यों के हिस्से में ग्रायेगा।
- 67. उत्पादन-शुल्कों के विषय में मेरा दूसरा बड़ा प्रस्ताव मोटर स्पिरिट, विलायकों (सोल्बेंट) और श्रन्य कई साधारण किस्म के स्नेहकों (लूकिकेंट) के बारे में हैं। तेल की श्रन्त-राष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुये, पैट्रोलियम और पैट्रोलियमजन्य पदार्थों के उपयोग में श्रिष्ठक से श्रिष्ठक किफायत बरतने की जरूरत है, यदि हमें विदेशी मुद्रा के श्रपने श्रष्ट्य साधनों को मुरक्षित रखना है। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना होगा, परन्तु यह तो हमारे लोगों को सहना ही पड़ेगा। श्रतः खपत को कम करने के लिये, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर स्पिरट पर शस्क की वर में 200 रुपये प्रति किलो लिटर या 20 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि कर दी जाये। ऐसा करने से चालू वर्ष में 36.30 करोड़ रुपये का श्रतिरिक्त राजस्थ मिलेगा।
- 68. कुछ विशेष क्वयनांक (बार्यालंग प्वाइंट) वाली स्पिरिटों का, जिन्हें विलायक तेल भी कहा जाता है, मोटर स्पिरिट में मिलाबट करने के लिये बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। इस दुरुपयोग को कम करने के लिये, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विलायकों के शुल्क की 45 [पये प्रति किलो लिटर को वर्तमान दर को बढ़ा कर 845 रुपये प्रति किलो लिटर कर दिया जाये। इस उपाय से चालू वर्ष में 4.25 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।
- 69. इसी प्रकार बिंद्या किरोसीन के साथ खिनज तारपीन तेल की मिलावट को रोकने के लिये खिनज तारपीन तेल पर 100 रुपये प्रित मेट्रिक टन का श्रितिरिक्त शुरूक लगाया जा रहा है। तरल पेट्रोलियम गैस के मामले में, मैं 20 प्रतिशत के मूल्यानुसार शुरूक लगाने का हटा कर उसके बदले 25 पैसे प्रित किलोग्राम की दर से परिमाणानुसार शुरूक लगाने का प्रस्ताव करता हूं। माफ किये हुये पेट्रोलियम से सीधे निकाले जाने लाले स्नेहक तेलों और ग्रीजो पर इस समय जिस दर से शुरूक लगता है वही दर श्रव से मिश्रिन स्नेहक तेलों, ग्रीजों श्रीर निस्तापित पेट्रोलियम कोक पर भी लागू होगी। किन्तु उपरोक्त वस्तुश्रों के निर्माण में काम ग्राने वाले पेट्रोलियम कोक पर भी लागू होगी। किन्तु उपरोक्त वस्तुश्रों के निर्माण में काम ग्राने वाले पेट्रोलियम कोक पर भी लागू होगी। किन्तु उपरोक्त वस्तुश्रों के निर्माण में काम ग्राने वाले पेट्रोलियम काक पर पाधार पादर्थों के सम्बन्ध में, उस शरूक को जमा माना जाएगा जो पहले ही चुका विया गया हो। मैं समझता हूं कि इन उपायों से 1971–72 में 9 करोड़ रूपये का ग्रातिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

- 70. इस समय कार्बन डाइग्रॉक्स।इड गैस पर णुल्क लगता है, परन्तु भ्रन्य गैसें, जैसे भ्रॉ-क्सीजन, क्लोरीन, एमोनिया श्रौर प्रशीतक गैसें शुरूक-मुक्त हैं, ये छूटें खत्म की जा रही हैं। फिर भी खवा के काम में श्रान वाली श्राक्सीजन श्रौर उर्वरक नैयार करने के काम में श्राने वाली एमोनिया आग भी शुरूक-मुक्त रहेंगी। इस उपाय से 1.60 करोड़ रुपये प्राप्त होने की श्राशा है।
- 71. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि शीशों के बर्तनों पर बुनियादी शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत और शीशे की चद्दरों और प्लेटों पर 15 प्रतिशत कर दिया जाए। शीशों के खोलों (शेल), शीशों के गोलों धौर प्रयोगशालाधों में काम धाने वाले शीशों के बर्तनों को प्रछूता छोड़ दिया जायेगा। गत वर्ष चमकदार और भनीटरी मामान पर शुल्क बढ़ाया गया था, परन्तु भोजन की मेज पर काम में ब्राने वाली वस्तुओं (टेबलवेयर) और चीनी मिट्टी की वस्तुओं को ज्यों-का-त्यों छोड़ दिया गया था। मैं इस वर्ष इस कमी को पूरा कर देना चाहता हूं। इन दोनों प्रकार की वस्तुओं पर अब समान रूप से 20 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा करेगा। इन दो परिवर्तनों से इस वर्ष हमें लगभग 3.15 करोड़ रुपय का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का धन्मान है।
- 72. हालांकि एयरकंडीशनरों पर 53.3 प्रतिशत की दर से शुल्क लग रहा है, परन्तु वाष्पिनिक प्रकार (इयेपोरेटिय टाइप) के कूलर श्रव तक शुल्क से मुक्त रहे हैं। इस भेद-भाव की मिटा दना ही उचित होगा । किन्तु मैं उन पर केयल 25 प्रतिशत की दर से ही शुल्क लगाने का प्रस्ताय करता हूं श्रौर साथ ही उनको विशेष उत्पादन शुल्क की ग्रदायगी से भी मुक्त कर रहा हूं। इसी प्रकार, श्रव तक येक्यूम फ्लास्कों पर भी शुस्क नहीं लगता था, श्रव उन पर भी मूल्यानुसार 15 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा करेगा। इसमें चालू वर्ष में 54 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
- 73. यह प्रस्ताव है कि साबुन पर शुल्क की वर्तमान प्रभावी दर की 11.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया जाय। इससे नहाने के साबुन की कीमतों में बहुत थोड़ी-सी ही वृद्धि होगी। घरेलू सामान और कपड़ा धोने के साबुनों को श्रष्ठूता छोड़ा जा रहा है। श्रांशिक छूट दिये जाने के कारण, कपड़े श्रादि धोने के पाउडरों पर शुल्क की प्रभावी दर, घरेलू समान और कपड़े धोने के साधारण साबुनों पर लगने वाली दर से भी नीचे बैठती है। श्रत: यह प्रस्ताव किया जाता है कि इस श्रांशिक छूट को समाप्त कर दिया जाये और इन पदार्थी पर फिर से पूर्ण सांविधिक दर से णुल्क लगाया जाए। साबुन और धुलाई-पाउडरों के संबंध में इन दो परिवर्गतनों से इस वर्ष के श्रेष भाग में 2,55 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की संभावना है।
- 74. यह भी प्रस्ताव है कि कुछ ग्रन्य विलास-वण्तुग्रों (लक्सरी ग्राइटम ) पर भी कराधान किया जाये। फोम के गददे बनान में बहुत ग्रिधिक काम ग्राने वाले लेटेक्स फोम स्पंज पर इस समय मूल्यानुसार 20 प्रतिशत गुल्क लगता है जो शुल्क की ग्रपेक्षाकृत काफी नीची बुनियादी दर है; मैं इस गुल्क-दर को दोंगुना करने का प्रस्ताव करता हूं। पालीयूरेथेन फोम ग्रौर इह फोम-विशेष से तैयार किये जाने वाले कितिपय उत्पादों पर भी इतना ही शुल्क लगाया जायेगा। रबड़ की प्लेटों बद्दरों ग्रौर पट्टियों पर गुल्क की बुनियादी दर को भी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। इन उपायों से 1971-72 में 2.60 करोड़ रुपये का ग्रिति-रिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

- 75. ऋाउन कार्क और पिल्फरप्रूफ ढक्कनो पर लगने वाले शुल्क को प्रति-इकाई 1 पैसा से बढ़ा कर 2 गैसा प्रति-इकाई करने का प्रस्ताव है। इस उपाय में 1.90 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की आशा है।
- 76. शृल्कों के ढांचे को पुक्तिमंगत बनाने के लिये कुछ शौर परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव किया जा रहा है। इनमें से कुछ पिवर्तन ये हैं—सुख ई गई डिज्बा-बंद और बीतलबंद साग-सिक्जिमीं पर श्रीर गुजूकीज शौर डेक्स्ट्रोज से बनी चीजो पर उत्तादन शृल्क लगाया जाना; स्टपल रेशे की कुछ किस्मी के लिय बुनियादी उत्पादन शृल्कः पर 50 पैसा प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलने वाली विशेष रियायत को हटा देना, सीमेंट पर लगने वाले शृल्क की 23.76 प्रतिशत की दर का पूर्णांकित करके 24 प्रतिशत कर देना, उनी धागे पर शृल्क की बढ़ा देना और इसके भार के कुछ श्रंश को वूलटोपों पर डाल देना, 60 श्रीर उससे कम बाट के बिजली के बल्बों को छोड़कर बाकी बल्बों पर लगने वाले शृल्क में परिवर्तन कर देना फ्लोर उससे कम बाट के बिजली के बल्बों को छोड़कर बाकी बल्बों पर लगने वाले शृल्क में परिवर्तन कर देना फ्लोरेमेंट ट्यूबों श्रीर बिजली के पंखों तथा श्रींखोगिक पंखों, पर 16 इच ब्यास के पंखों छोड़ेकर, शृल्क की दर बड़ा देना, श्रीर तार श्रीर केबल बनानें के काम में श्राने वाले ताम्बे पर प्रति टन 500 रुपये क हिसाब से मिलने वाली रियायत को हटा देना। इन विभिन्न उपायों से कुछ मिलकार 6 करोड़ रुपये से उपर की राजस्व प्राप्ति होगी।
- 77. मैंने पहले बताया था कि शहरों में ही नहीं अपितु गांवों में भी आय की असमानताओं को शीधाता से कम करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए एक तरीका यह है कि अधिक धनी किसानों द्वारा खेती के काम में लाये जाने वाले पदार्थी और उपकरणों पर, चयनात्मक आधार पर, अप्रत्यक्ष कर लगाएं जाएें। अतः मैं खेती के काम आने वाले ट्रैक्टरों पर 10 प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं; इस उपाय में चानू वर्ष में 3 10 करोड़ रुपये के राजम्ब की प्राप्ति होने की मंभावना है।
- 78. राजस्य में बृद्धि करने के लिए घनेक नई यस्तुग्रों को केन्द्रीय उत्पादनगुल्को की परिधि में लाया जा रहा है। यस्तुग्रों ग्रीर गुल्क की दरों को इस प्रकार चुना जा रहा है कि मूल्य—स्तर पर इन गुल्कों का वास्तिविक प्रभाव नगण्य ही हो। जिन यस्तुग्रों को मैं इस कोटि में लाना चाइता हूं उनमें से कुछ ये है:—सुगन्धित केण तेल, गंपू, लिपिस्टिक, प्रेसर कुकर, ताश, जिप जंजीरे, फीटो लेने के कैंगरे, सिनेमा प्रक्षेपी ग्रीर लिनोलियम। हम में से बहुत थोड़े लोग होंगे जो इस विषय में ग्रपनी राय देने का साहस करेंगे कि ग्राधुनिक भारत में रहन—सहन की ग्रीली, गित ग्रीर स्तर में सुधार करने के कार्य में सुगन्धित केश तेल, लिपस्टिक या ताश के पत्तो का क्या योगदान रहा है। परन्तु मुझे विश्वास है कि सम्मान्य सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि इनमें से ग्रधिकांश वस्तुएं शान—शौकत से रहने वालों के चोंचले हैं; इन वस्तुग्रों पर उत्पादन गुल्क लगाने में ग्रधिकांश जन—समुदाय के जीवन स्नर पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
- 79. इसी कारण से, मैं कुछ विशेष प्रकार के सिले-सिलाये कपड़ों पर णुल्क-लगाने का प्रस्ताब कर रहा हुं जो अधिकतर संपंतव्यक्तियों द्वारा ही खरीदे जाते हैं। किन्तु, छोटे निर्माताओं के हितों की रक्षा करने के लिये यह निश्चय किया गया है कि यह णुल्क उन्हीं सिले-सिलाये कपड़ों पर लगेगा जो विजली की गन्ति से तैयार किए जाएंगे और पंजीकृत व्यापार चिन्ह (ट्रेड मार्क) या छापन्ताम (ब्रांड नेम) से बेचे जाएंगे। छोटे उत्पादकों को एक और रियायत के रूप में, एक विशिष्ट मूल्य तक की निकासियों को उत्पादन-शुल्क से अलग रखा जाएगा बर्गत कि संबंधित एकक का कुल वार्षिक उत्पादन एक निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक न हो।

- 80. मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि बहुत सी उत्पादक-वस्तुओं, जसे बाल श्रीर रोलर वेयिशीं, बोल्टों, दिविश्यों श्रीर पेचीं, विजली-रोधी श्रीर चिकित्सेतर चिपकने वाले फीतों, वेहिंडंग इसेक्ट्रोडों, साण-चकों श्रीर मोटर स्टार्टरों पर उत्पादन शुल्क लागू किया जाए, क्योंकि इन वस्तुओं से शंतत: निर्मित उत्पादों पर कर लगाना कठिन है श्रीर इस समय हम कुछ संभावित राजस्व को खो रहे हैं। इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क की दर 10 प्रतिशत होगी। यह भी प्रस्ताव है कि विजली के मीटरों, टाइपराइटर के रिवनों, मोजेक टाइलों, फोर्क लिफ्ट श्रीर प्लेटफार्म ट्रकों श्रीर नोटर गाड़ी के कुछ कलपूजों श्रीर उपसाधनों पर भी 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगा दिया जाए। जब कभी श्रावश्यक होगा ती छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा उसी प्रकार की रियायत देकर कर ली अएगी जैसी रियायत का उल्लेख मैंने सिले-सिलाये कपड़ों के संदम में किया था।
- 81. उत्पादन-शुल्क-योग्य रमावनों की सूची में चार भ्रोर रसायन शामिल किए जा रहे हैं भीर उन पर 10 प्रतिशत की घर से शुल्क लगेगा । कपूर भीर पौदीने के सत्त (मेन्यल) पर भी ऐसा ही शुल्क लगेगा।
- 82. नए उत्पादन-शुल्क लगाने के इन उपाझों हो कुछ मिलाकर 15 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की संभावना है।
- 83. अब में एक तए और महत्वपूर्ण उपाय की घोषणा करना चाहता हूं जो बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के कार्यक्रम के खर्च को पूरा करने के अभिप्राय से अपनाया जा रहा है। मैं संगठित क्षेत्र को रोलर पलोर मिलों द्वारा तैयार किए गए मैंदे पर 10 पैसे अति किलोगाम शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस विशेष प्रकार के आटे की खपत, आमतौर पर, अधिक धनवान धर्मों में होती है अयवा वह मिठाइयां बनाने के काम में आता है; एक और वस्तु जो इस मैंदे से बनती है वह है डवन रोटी; इसकी खपत भी अधिक नर ऊंची आय वाले वर्गों तक ही सोमित है। मुझे विश्वाश है कि इस प्रकार शुल्क लगाने से जो थोड़ा-सा खर्च बढ़ेगा उसे ये उपभोक्ता प्रसन्नता पूर्वक सह लेगे क्योंकि इसके फलस्वरूप केन्द्र के हिस्से में आने वाला 7.4 करोड़ रुपये का राजस्व, बच्चों के कल्याण कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, इस उपाय से राज्यों को भी लगभग 1.8 करोड़ रुपए की प्राप्त होगी।
- 84. अब मैं उत्पादन गुल्क सम्बन्धी कुछ रियायतों का उल्लेख करूंगा जो मैंने वाछनीय समझी है। साबुन बनाने में हल्कें तेलों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रौर इसके द्वारा श्रायातित टलों श्रौर तेलों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उस स्थित में साबुन पर उत्पादन गुल्क के भार को कम कर दिया जाये जब कि उसके निर्माण में एक निश्चित न्यूनतम सीमा तक, नीम भौर साल के जैसे हलके तेलों का उपयोग किया गया हो। लघु उद्योगों के क्षद्र में सस्ती किस्म के साबुन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सोडियम सिलिकेट पर शुल्क की दर को कम कर दिया जाएगा। बिनौले के श्रीवक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बनास्पती बनाने में इस तेल का प्रयोग करने के लिए इस समय उत्पादन-गुल्क में जो रिबेट मिल रहा है, उसे बढ़ा दिया जाएगा। एक ऐसी ही रियायत बान की भूसी के तेल के बारे में भी देने का प्रस्ताव है।

- 85. सूती कपड़ा बनाने के लिए पावर लूमों का प्रयोग करने वाले लघु और सीमान्तिक (मार्जिनल) एककों को कुछ राहत देने के उद्दृश्य में, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जिस एककों में चार नक पानरलम लग हुए हों उन पर लगाए जाने वाले संयुत (कम्पाउण्डेड) उत्पादन शुल्क की दर 50 रुपए से घटाकर 10 रुपए प्रति लूम प्रति वर्षे कर दी जाए। चार से श्रीधक पावरलूम वाले एककों के मामले में संयुक्त शुल्क वर्तमान दरों से श्राधा होगा । स्वाधीन संसाधकों (प्रोसेसर) को इस समय उपलब्ध होने वाली रियायत को भी युक्तिसंगत बनाया जाएगा। कसीदाकारी और चमड़े के कपड़े बनाने वालों के लिए भी कुछ-एक सीमान्तिक रियायतें धी जा रही है।
- 86. इन सब राहतो और रियायतों के दिए जाने के फलस्वरूप, वर्षिके शेष भाग में राजकोष में लगभग 1.50 करोड़ रुपए की कम प्राप्ति होगी।
- 97. इसके साथ ही, उत्पादन मुल्कों के सम्बन्ध में प्रस्तावित परिवर्तनों की काफी लम्बी मची समाप्त होती है। उत्पादन मुल्कों से सम्बन्धित इन सभी प्रस्तावों को एक साथ हिसाब में लेने के बाद अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष के मेप भाग में केन्द्र के लिए लगभग 89 करोड़ रुपए की छौर राज्यों, के लिए 43 करोड़ रुपए की फुल प्राप्ति होगी।

## (ग) प्रभ्य उपाय

- 88. प्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्कों ग्राँर उत्पादन शुल्कों पर विचार करने के बाव भी में समझता हूं कि ग्रभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ग्रभी मुझे सम्मान्य सदस्यों के सम्मुख एक नया प्रस्ताव पेश करना है जो पूरी तरह उत्पादन शुल्क जैसा नहीं है। यह कर मैं विदेश याद्वा पर लगाना चाहता हूं। यह कर रुपयों में खरीदी गई सभी टिकटों पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत की दर से लगाया जायगा; विदेशी मुद्रा में खरीदी गई टिकटें इस कर से मुक्त रहेंगी। केवल एक दूसरी वड़ी छूट छात्रों ग्रौर वैज्ञानिकों को दी आयगी। इह उपाय बाद में श्रिध्मिचित की जाने वाली किसी तारीख से लागू किया जायगा। इस उपाय से लगभग 7.00 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने का ग्रनुमान है। यदि कोई सम्मान्य सदस्य यह महसूस कर रहे हों कि मैं उस सुविधा को छीन रहा हूं जो बहुत सी हवाई कम्पनियां रियायती किराये के रूप में ग्रनुगह पूर्वक देती हैं तो मैं उनको यह श्रास्वासन देना चाहूंगा कि मूल्यानुसार प्रस्थावित कर के फलस्वरूप रियायत का मूल्य निरपे के रूप में वस्तुत: बढ़ जाएगा।
- 89. श्रीर श्रव मैं उन श्रंतिम प्रस्तावों पर श्राता हूं जो मुश्चे मेरे श्रपने साथी संचार मंती—महोदय की श्रोर से पेश करने हैं। सम्मान्य सदस्यों को विदित है कि डाक श्रौर तार शाखाशों ने पिछले वर्षों में भारी घाटा दिखाया है श्रीर चाल वर्ष में भी उन्हें 15 करोड़ रुपए तक का घरटा होने की सम्भावना है। डाक सार श्रिभाग की दरों के ढांचे की जांच करने के लिए नियुक्त की गई शुल्क-दर जांच समिति (टेरिफ इन्क्वायरी कमेटी) ने श्रीर प्रशासनिक सुधार श्रायोग ने भी यह सिफारिश की है कि डाक-तार विभाग को वित्तीय क्षमता प्राप्त करने की जरूरत है श्रीर यह भी बांछनीय है कि उनके कार्यचालक से लाम प्राप्त हो। इसलिए शुल्क-दरों में कुछ बढ़ोत्तरी करना अनिवार्य है। इस बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव करते हुए हमने समाज के श्रपेक्षाकृत कम सम्पन्न वर्गों की नमस्यात्रों को ध्यान में रखा है श्रतः पोस्टकाडों, लेटरकाडों श्रीर पत्नों की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। श्रधिकतर डाक-वस्तुग्नों के रजिस्ट्री-शुल्कों, श्रीर तार श्रीर टेलीफोन की शुल्क-दरों में ही वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। 400 ग्राम के लिए रजिस्ट्री शुल्क में उपैर पांल-शुल्क में 10 पैसे की वृद्धि की जा रही है 8 से श्रधिक शब्दों वाले तारों के शुल्क में ग्रीर टेलीफोन, टेलीफिन्टर श्रीर टेलेक्स सेवाग्रों के किराए में भी मामूली गमायोजन किर जा रहे हैं। प्रस्तावित परिवर्तनों का ज्ञापन जलट-पत्नों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

- 90. जहां तक संघ के बजट का सम्बन्ध है, पेश किए गए प्रस्तामों से 1971-72 में कुल 177 करोड़ रुपए का प्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। ग्रतः मैंने बजट में पहले 397 करोड़ रुपए का जो घाटा बताया था वह श्रव घटकर 220 करोड़ रुपए रह जायगा।
- 91. श्रव मैं श्रपने भाषण के श्रंतिम भाग पर पहुंच गया हूं। सच तो यह है कि यह बजट सैयार करना मेरे लिए एक कठिन कार्य था। इसमें श्रनेक प्रकार के राजस्व सम्बन्धी प्रस्ताव किए गए हैं श्रीर यह निश्चत है कि नए कराधान का प्रभाव कुछ क्षेत्रों पर काफी श्रिष्ठक माला में पड़ेगा। किन्तु, मुझे सम्मान्य सबस्यों को इस बात का स्मरण करा देना चाहिए कि पिछले वर्ष श्र्यंच्यवस्था में मूल्य-वृद्धि काफी चिन्ता का विषय बनी रही है, इस लिए यह श्रावश्यक है कि बजट में घाटे को उचित सीमाओं में ही रखा जाए। श्रायोजना के श्राकार में पर्याप्त वृद्धि करके श्रीर पहले से श्रधिक रोजगार के श्रवसर प्रदान करके हमें जनता के प्रति श्रपने दाित्व को पूरा करना ही है; साथ ही इस समय पूर्व बंगाल की घटनाओं श्रीर किकान्त व्यक्तियों के बढ़ते हुए प्रवाह की श्रकल्पनीय समस्या भी हमारे सामने है।
- 92. तथापि, राजस्व-नीति केवल या प्राथमिक रूप से ऐसा विषय नहीं है जिसके जरिए राष्ट्रीय राजकोष से की जाने वाली अनिवार्य मांगों को पूरा करने के लिए ही साधन जुटाए जाएं। अपितु इसके माध्यम से बड़े उद्देश्य भी पूरे किए जाने चाहिए और अर्थव्यवस्था को भी वांखित दिशाओं में मार्ग धर्मन मिलना धाहिए। श्राय, धन और श्राधिक शक्ति के क्षेत्र में इस समय जो असमानतायें विद्यमान है उन्हें काफी हद तक दूर करने के लिए और श्राडम्बरपूर्ण उपभोग को कम करने के लिए राजस्वनीति का विशेष उपयोग किया जाना चाहिए। इसीलिए मैंने, अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में, कई उपाय प्रस्तुत किए हैं हो सकता है कि राजस्व-प्राप्ति की दृष्टि से श्रस्य अवधि में उनका महत्व बहुत श्रधिक न हो, परन्तु वे न्याय-पूर्ण समाज की स्थापना करने की दिशा में महत्वपूर्ण कथम साबित होंगे। श्रप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में भी हमारे शोधन-श्रंप पर पड़ने वाले दबावों की कम करने आदि के उद्देश्यों को ध्यान में रखा, गया है; यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया गया है कि श्रतिरिक्त भार का थोड़ा-सा ग्रंश ही जनसाधारण को उठाना पड़े।
- 93. यह दावा करना शायद ही संभव हो कि केवल बजट सम्बन्धी नीति के जिए और वह भी एक ही बजट के द्वारा, एक नई सामाजिक और ग्राधिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इस ग्राकार के बजट में उन सब उद्देश्यों का समाधान कर सकना भी किटन है जो हमने सामने रखे हैं। फिर भी, मैं ग्राशा करता हूं कि तात्कालिक तथा श्रति महत्पूर्ण ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति का प्रयत्न करते हुए मैं एक सच्चे समाजाववी समाज के स्थीकृत लक्ष्य की ग्रोर ग्रग्रसर होने के कर्तव्य से विमुख नहीं हुग्रा हूं।

# Budget 1971-72 Speech of Minister of Finance 28th May, 1971

Sir.

On the 24th of March this year, I had presented to the Honourable House an interim Budget for 1971-72. I had then assured Honourable Members that the Budget proper to be presented in the current Session will provide for a significant increase in the outlays on development and social welfare over and beyond what the interim Budget had indicated. It is in fulfilment of this commitment that I rise before you today.

### Economic Conditions

- 2. Earlier this week, the Government have laid on the floor of the Honourable House the Economic Survey for 1970-71. The Survey shows that the economy presents in general a promising picture indeed and that it is now better poised to tackle the tasks ahead than at any other time in recent years. We have once more been able to fulfil during 1970-71, the target set in the Fourth Plan with respect to the overall rate of economic growth. In agriculture, progress has been maintained; foodgrains production has continued to expand at a most satisfactory rate. In the industrial sector, lack of certain essential raw materials has hampered production in some areas and there is still under-utilisation of capacity in a few other areas. But new grounds have been broken in our import substitution efforts, and recovery from the years of recession in the middle 1960's is considerable. Besides, the growth in the small-scale sector is most encouraging. Enough symptoms abound which indicate that once a significant improvement occurs in the scale of public investments, industry as a whole will surge forward. After a few initial set-backs, there has been a remarkable spurt in exports towards the later months of the year. Better organisation is, however, still the major outstanding task for both industry and exports. Apart from raw material shortages and procedural delays, we have also to face problems of low scales of operations and high unit cost in some industries. Cost reduction and improvement in efficiency are thus vital for imparting a new dynamism to industrial growth and exports.
- 3. In agriculture too, there is yet no occasion to relent on our efforts. We must continue the search for high-yielding varieties of paddy which will prove durable in our varying agro-climatic conditions. Irrigation facilities will have to be expanded to ensure the extensive, propagation of double cropping. Our search for better pest-resistant qualities of seeds for millets must go on. The greatest area of responsibility will lie in improving the productivity per hectare of pulses and the cash crops, including cotton, oilseeds and jute. During 1970-71, there was a marked stability—occasionally even a certain fall—in foodgrain prices. In fact, but for the Government's price support operations intended to protect the farmers, there was an overall increase in the general price level largely induced by the shortage in the availability of commercial crops. Against this background, we canot accelerate our rate of growth with price stability unless we raise the output of commercial crops.
- 4. On the external side, while we can take credit for repaying our outstanding obligations to the International Monetary Fund, our balance of payments is not as satisfying as it was at the end of 1969-70. Exports have shown a remarkable improvement. At the same time, with the rising tempo of industrial activity, imports have been going up. Outstanding import licences suggest that there will be a further increase in imports during the current year. Because of shortage in steel, cotton, oils and oilseeds, we have had to plan for much larger imports than originally envisaged. Fresh aid allocations have declined during the past year even as the burden of debt servicing has continued to mount. Net aid

available to finance imports has, therefore, shrunk. Thus we can scarcely afford to relax in the matter of a prudent management of our balance of payments.

### Reorientation of Policies

- 5. The massive mandate which this Government received from the people three months ago was a mandate for socialism, a mandate for rapid economic growth matched by increased social justice. There can be little doubt that social justice must begin with increasing the opportunities of job and work for every one. A good deal has been done in the course of the past year to initiate measures for creating gainful work for the urban unemployed as well as the rural under-employed. During the past year, the nationalised banks have expanded their scale of operations so as to provide more credit to the hitherto neglected sectors and for purposes of self-employment. They intend to do much more in future. A crash programme for rural employment has been announced and the Government's broad objective is to ensure employment to at least one person in each family in all parts of the country. At the same time, the Government is determined that such schemes for creating employment do not take the form of ad hoc measures but contribute to the accretion of additional physical assets in the countryside in the form of new roads, land reclamation, land development, drainage etc.
- 6. Honourable Members will also remember that special works programmes were introduced last year to improve job opportunities in the countryside, particularly for the small farmers and in the backward areas. These schemes will continue. In addition, as I shall describe presently, we propose to make a special budgetary provision for assisting the educated unemployed in their search for a constructive opportunity to serve the nation.
- 7. The largest stimulus to employment can, however, come only by increasing the tempo of economic activity all round. It is therefore essential that expenditure under the Plan is maintained on projected levels and that no shortfalls occur. I am afraid that our performance in 1970-71 in this respect leaves much to be desired. While I am proposing to increase significantly the Plan outlays over what was allocated last year, the emphasis has to be even more on the timely implementation of Plan projects for which budgetary provision is being made.
- 8. Faster growth and greater social justice will be elusive goals unless pursued in a milleu of relative price stability. We can scarcely ignore the adverse effects of unabated price increases on both investment and income distribution. Inflation also dislocates attempts to increase the efficiency of production and to lower unit cost, which in turn affects exports. There is therefore need for continuous vigilance. The drive for a faster rate of growth in this sense, therefore, blends with the parallel goal of achieving price stability. In this task, we must also keep under examination the operation of the monetary forces.
- 9. Our procedure for formulating annual Plans is itself in the nature of a reasessment of Plan priorities and objectives. At the present juncture, when we have just received a new mandate, it is also necessary to make a fresh appraisal of the Plan as a whole. The emphasis from now on has to be on measures which will speed up the process of implementation of projects, foster the expansion of employment opportunities and reduce disparties, including regional dispartities. Honourable Members are aware of the various steps taken in recent years for encouraging growth, including growth of industry in the backward areas through allocation of Plan assistance and similar fiscal and other means. The same objective has to be kept in mind in the allocation of our foreign exchange resources including those mobilised through external assistance. Schemes intended for backward areas have to be given due consideration at the stage of the formulation of the Plan itself, so that in the general allotment of internal and external resources under the Plan, the different parts of the country, and particularly the retarded regions, get their due share.
- 10. Our public sector enterprises have deepened and widened the industrial base of the economy and achieved certain basic social objectives. Efficient performance on the part of these enterprises is crucial for the Government's overall development effort. The extent of buoyancy that can be added to the economy each year will be largely related to the ability of the public sector to implement the Plan proposals. Administrative and procedural delays which hold back progress of these enterprises are thus matters of considerable concern. Similarly, the public sector has to yield a sizeable surplus, since this surplus is

a key source of future growth. During the past year, a number of steps have been taken to raise the general efficiency of public enterprises. Increasing attention is being devoted for the proper maintenance of inventiones as well as of plant and machinery in each public sector unit, and towards tackling the problem of personnel management and industrial relations. In regard to the latter, we would certainly like to have the advice and counsel of trade unions. They have an equal stake in the efficiency of the public sector. I hope that, with their cooperation, it will be possible to initiate a new chapter of industrial relations in our public enterprises.

- 11. A large segment of the commercial banks is also now a part of the public sector. Here too, I would seek the cooperation of the trade union leaders to improve the efficiency of the banking system. A beginning was made recently when I initiated a dialogue with the employees and the management of the banks; our discussions covered such areas as credit planning and deposit mobilisation. I propose to continue this practice. The new Boards of Directors, the composition of which will be announced soon and which will include representatives of the Award staff and officers, will, I hope, carry forward the task of improving the procedures and policies of the banks along intended lines.
- 12. Each of the nationalised banks has been urged to have an annual credit plan which could ensure that the credit apportioned to the different sectors, and particularly the sectors neglected hitherto, is in conformity with their needs and at the same time within the norms of monetary expansion. The Committee appointed by the Reserve Bank of India to suggest credit schemes for promoting self-employment has made a number of valuable suggestions which are being given shape to by the commercial banks. Another committee which was asked to recommend a scheme of differential lending rates for helping the smaller borrowers and the weaker sections of the community has just submitted its report. A Credit Guarantee Corporation has been set up with effect from first April to underwrite the advances offered by banks to small borrowers. Honourable Members are also aware that the Government have recently framed the guidelines for the conversion into equity of loans offered by public financial institutions. These guidelines should go a long way to promote the establishment of a joint sector to which we attach considerable significance.
- 13. Honourable Members, I am sure, are happy with our decision to take over the business of general insurance in the country. This decision marks a culmination of the process which was started when we nationalised the Imperial Bank of India and the life insurance business and to which we gave a major thrust less than two years ago through nationalisation of major commercial banks. With these measures, virtually all the savings of the people mobilised by financial institutions can now be deployed in accordance with national priorities.

#### Revised Estimates, 1970-71

- 14. In the Interim Budget, I had indicated that the year 1970-71 will close with an overall deficit of Rs. 230 crores. The Budget documents I am presenting today repeat from the Interim Budget the Revised Estimates for 1970-71, since actuals are not yet available in most cases. According to the latest indications, however, the overall deficit for 1970-71, I am afraid, may be of the order of Rs. 270 crores.
- 15. While presenting the Interim Budget, I had occasion to express concern over the fact that a number of States were over-drawing their accounts with the Reserve Bank of India. I regret to say that despite the increased special assistance of Rs. 195 crores to the States during 1970-71, there has been no abatement in the States' recourse to overdrafts from the Reserve Bank as will be evident from the fact that, at the end of last March, as many as 14 States had overdrafts aggregating to Rs. 260 crores. The special assistance to States, which was designed to help them to fulfil their targets of Plan outlays, is to taper off in the coming years. In this context, the problem of overdrafts assumes an additional gravity. I would appeal to the States to maximise their efforts for raising additional resources and to enforce the strictest discipline on the growth of non-Plan expenditure.

### Budget Estimates, 1971-72

- 16. Honourable Members will recall that in the Interim Budget I had provided a sum of Rs. 1,195 crores for the Central Plan for 1971-72, that is, at the same level as in the Budget for 1970-71. I had then stated that the provision for the Central Plan for the current year was to be augmented following a review of requirements and resources. I propose to raise the outlay under the Central Plan by Rs. 155 crores, that is, to Rs. 1.350 crores. This represents an increase of more than Rs. 300 crores over the likely actual level of expenditure in 1970-71. The more important areas where the budgetary provisions have been significantly raised over what was provided in the Interim Budget include shipping (Rs. 16 crores), ports (Rs. 13 crores), roads (Rs. 10 crores), mines and metals (Rs. 9 crores), health and family planning (Rs. 12 crores), Posts and Telegraphs (Rs. 11 crores), agriculture (Rs. 32 crores) and food procurement (Rs. 18 crores). I had already provided in full in the Interim Budget the sum of Rs. 785 crores towards Central assistance for the Plans of the States and the Union Territories, as against a provision of Rs. 711 crores in the Budget for 1970-71.
- 17. For creating immediate employment opportunities, even a larger Plan outlay may not be enough in the short period. I have therefore decided to add a further thrust to the public sector outlay which could both generate additional employment and provide relief to the weaker sections of the community. For the crash programme for rural employment a provision of Rs. 50 crores was already made in the March Budget. But the problem of unemployment is equally acute among our educated young men and women. We are determined not to permit them to be a lost and frustrated generation. We propose to assist them actively so that they might set themselves up in gainful creative endeavours which would at the same time accelerate the pace of economic progress of the country. To this end, in the Budget I am now presenting, we propose to allot a further sum of Rs. 25 crores for schemes specially designed to suit the educated unemployed including engineers and technicians. The details of these schemes are being worked out in consultation with the Planning Commission and the Ministries concerned.
- 18. Honourable Members will be glad to know that the provision of Rs. 4 crores made in the Interim Budget for a nutrition programme for children is now being raised to Rs. 10 crores, and included in the Plan. I have no illusion that even this larger provision will mean much more than a beginning in the task of protecting and nutruring the health and welfare of the poor children. I do hope that, in this matter, we will be in a position to do substantially more in the coming years. I might also mention here that we propose to reserve 2b per cent of fresh admissions to public schools for meritorious candidates, who will be offered Government scholarships.
- 19. The special provisions made last year for improvement of slums are being maintained. The work of the Calcutta Metropolitan Development Authority will be pursued with vigour. I would also like to state here that the Government would consider sympathetically proposals for a similar improvement in living conditions for slum dwellers in other metropolitan cities and towns; if State Governments and municipal bodies could initiate viable schemes for this purpose, we will consider the question of financial accommodation.
- 20. Finally, I have to refer to the tragedy that has been enacted over the past two months in East Bengal representing some of the darkest episodes in human history. Already, some three million evacuees have crossed over the borders. In fact the number is now nearly four million. It is our hope and endeavour that all these unfortunate people will be able soon to return to their homes and hearths in dignity and honour. Meanwhile, we shall do our utmost to offer succour and relief to all those who have taken temporary shelter with us. It will clearly be beyond our capability to meet on our own the financial burden involved. We regard it as the responsibility of the international community to share with us this burden. In the Budget, I have tentatively made a provision of Rs. 60 crores for providing relief to the evacuees from East Bengal. For the present, we have taken credit on the revenue side to the extent of Rs. 20 crores which we expect will accrue to the Budget by way of external assistance for the relief of the evacuees. In addition, it is our hope that substantial supplies from abroad will be available for providing relief without being routed through the Budget. Honourable Members will note that the provision we have made will suffice only for a limited period and that a considerably higher order of assistance from the international community will be necessary.

- 21. Let me now sum up the overall budgetary picture as it emerges following the increase in the Plan outlay, the provision for employment assistance, and certain inescapable additions to the non-Plan items of expenditure since the presentation of the Interim Budget in March. Apart from the provision for evacuee relief, I might mention in particular the addition in the expenditure on account of food subsidy, which is now placed at Rs. 30 crores instead of Rs. 10 crores as indicated in the Interim Budget. On present reckoning, the revenue receipts in 1971-72 are likely to be of the order of Rs. 3,562 crores. Expenditure to be met from revenue will amount to Rs. 3,587 crores. Thus the revenue surplus, placed in the Interim Budget at Rs. 114 crores, will now turn into a deficit of Rs. 25 crores. On the capital side, collections under the various small savings schemes are now expected to be Rs. 180 crores as against Rs. 155 indicated in the Interim Budget correspondingly, however, loans to the States will also go up by Rs. 16 crores, so that the net increase under this head will be only Rs. 9 crores. I have also taken credit for an additional accrual of Rs. 40 crores under PL 480 receipts representing largely the spill-over from 1970-71. Total capital receipts, inclusive of loans and advances and transactions under various debt deposit heads, are now placed at Rs. 2,024 crores and total capital expenditure, including loans and advances, is estimated at Rs. 2,396 crores. The capital budget will, therefore, show a deficit of Rs. 372 crores as against Rs. 354 crores in the Interim Budget. The over-all budgetary gap, taking revenue and capital accounts together, will now be of the order of Rs. 397 crores. This takes into account the effect on the Central Budget of the changes in Railway fares and freight rates announced a few days ago and of changes in the Post and Telegraph tariff to which I will refer a little later.
- 22. Honourable Members, I am sure, would not like me to leave uncovered a deficit of this magnitude in the Budget. I will, therefore, seek their indulgence if I have now to turn to what all of you, I am sure, are waiting for, namely, proposals to bring down the deficit to a more tolerable order.
- 23. The task of raising additional resources through fresh imposts on the people is the least enviable of a Finance Minister's responsibility. If I still have to approach this House with proposals to raise additional resources, it is because of the imperatives of the situation, including the need to augment the Plan outlay, to create additional employment opportunities and to offer succour to the evacuees from East Bengal.

### General Principles

- 24. In framing these proposals, I have endeavoured to follow certain broad principles. These are:
  - (a) The tax structure must be simplified and rationalised in such a way that the burden of assessment for the assessee as well as the tax collector and the opportunities for evasion are minimised;
  - (b) The overall burden of taxation must be distributed amongst the different sections of the community in such a manner that, in the process, there is an appreciable scaling down of the concentration of economic power and reduction in the inequalities in income and wealth: and
  - (c) The incidence of the fresh imposts should not, as far as possible, disturb the general level of prices of essential goods.
- 25. Accordingly, the concentration of the additional tax effort, to the extent feasible, should be on direct taxes, particularly on the affluent groups, and on such categories of indirect taxes as affect the luxury and near-luxury commodities. In so far as we succeed in limiting the burden of indirect levies on the latter group of commodities, we are also able to achieve in part the other objective of improving the structure of income distribution in society.

### Tax Administration

- 26. The tightening and streamlining of tax administration has two facets. First, at heaps to garner additional yield from the existing tax sources and thus makes it less necessary to look for fresh tax heads every year. Second, since it is generally the well-to-do and the rich who avoid and evade taxes, a tightening of tax administration, including closing of loopholes, would compel them to part with a larger proportion of their incomes and assets and would therefore further one of the overriding objectives of fiscal policy.
- 27. Undervaluation of property has been one of the means to evade wealth tax, capital gains tax and stamp duties. It has also been an important avenue for the circulation of black money. This practice could be greatly discouraged if Government had the power to acquire properties at prices that correspond to what is recorded in sale deeds. Accordingly, we propose to move a Bill during the current session to acquire this power. I hope it would not be considered dishonourable to take a dishonest man at his word.
- 28. In pursuance of the Administrative Reforms Commission's recommendations, it is also proposed to sponsor legislation in the current session to discourage benami holding of property. If, at the time of assessment, a person fails to declare income from a piece of property or the property itself so as to evade payment of income and wealth taxes, the intended legislation will debar him from enforcing his claim to such property in a court of law.
- 29. Pursuant to the recommendations of Administrative Reforms Commission, we further propose to transfer the work of recovery of arrears of estate duty from the State Governments to the Income Tax Department at the Centre. Since, in this matter, we can move only with the concurrence of the State Legislatures, a Bill is being drafted for circulation among the States.
- 30. It is proposed to strengthen the Valuation Cell located in the Central Board of Direct Taxes for making valuation of buildings in order to enable it to extend its activities and speed up valuations in cases involving the assessment of wealth tax. For assessment of income tax, under the new procedure which has cone into effect from the current year summary assessments will be completed in most cases which do not involve substantial points of dispute, and only a small proportion of the cases will be subjected to a sample scrutiny subsequently. This will enable the Income Tax Officers to devote correspondingly more time for cases involving substantial revenue.
- 31. In the field of excise duties, I propose to set up a Committee to review the Self Removal Procedure scheme, which has been in operation for the last two to three years, with a view to suggesting improvements which could reduce leakage of revenue. A Study Team, which considered the issues relating to over and underinvoicing, have made a number of suggestions for checking the leakage of foreign exchange through manipulation of invoice values. The Government will give early consideration to implement its recommendations. With a similar purpose, a comprehensive review is being undertaken of the Foreign Exchange Regulation Act; and we propose to introduce soon a Bill to amend several provisions of this Act.

### Consultation with States

- 32. In the past, at the Centre, we have taken several fiscal steps to discourage the growth and concentration of excessive income and wealth in a few hands in the urban areas. The constitutional prerogative of the Union Government to initiate measures for similar reforms in the countryside is however severely restricted. But this does not mean that some of the present anomalies must continue, or that we can be oblivious of growing inequalities in rural areas. Ultimately, the basis of tax has to be the size of income or wealth irrespective of whether it is derived from agricultural or non-agricultural sources.
- 33. Similarly, there are constitutional limitations on the powers of the Centre to tax services even when these are of a luxury or semi-luxury character. As the States and the Centre have to share the responsibility of raising resources for economic development, it is the duty and obligation of the Centre to point out to the States untapped resources for mobilisation where the Union Government itself is precluded by the constitutional provisions to impose any levy. It is my intention to consult and seek the advice of the State Finance Ministers on the entire range of these issues and to remain in continuous touch with them so that a concerted view is taken

### Direct Taxation

34. I now come to the new proposals in respect of direct taxation. If we are going to make an effective dent on the problem of income in-equalities in our society, we cannot possibly flinch from deploying increasingly the instrument of direct taxation. The proposals that I am outlining will have only a limited yield of revenue in the current year. Over a number of years, however, the cumulative effect of these proposals will be to raise revenue of a considerable order; what is much more significant, they will bring about a significant change in the distribution of disposable income and wealth.

### (a) Taxation on Income and Wealth

- 35. In the field of personal income taxation, the rate of surcharge in the case of individuals as well as Hindu undivided families is being increased from 10 per cent to 15 per cent provided the total income exceeds Rs. 15,000 per annum. In a full year, the impact of the proposal will be to provide an additional Rs 20 crores to the exchequer; for 1971-72, the revenue yield is expected to be around Rs. 12 crores.
- 36. I also want to take this opportunity to increase the tax on capital gains, which are a species of unearned income. The deduction from long-term capital gains allowed in computing the taxable income of non-corporate assessees is being reduced from 45 per cent to 35 per cent where such gains relate to lands and buildings and from 65 per cent to 50 per cent in respect of other capital gains.
- 37. The incidence of tax on long-term capital gains will be increased in the case of companies as well. This increase is being brought about by raising the rates of tax from 40 per cent to 45 per cent in respect of gains relating to lands and buildings and from 30 per cent to 35 per cent in respect of other gains.
- 38. I have some fairly stiff proposals regarding wealth tax. If a significant reduction in the concentration of wealth is to be brought about, it is essential that the taxation of wealth is made more rigorous. Honourable Members will recollect that last year's Budget made a beginning in this direction by raising the rates of additional wealth tax on urban property. This year, I propose to raise drastically taxation on siabs of net wealth above Rs, 15 lakhs, where the rate of tax will now be uniformly 8 per cent as against the current rates of 4 per cent on net wealth between Rs, 15 lakhs and Rs, 20 lakhs and 5 per cent on net wealth above Rs, 20 lakhs. I also propose to include in net wealth for purposes of taxation the first Rs, 1 lakh of wealth in the case of all individual assessees and the first Rs, 2 lakhs for Hindu undivided families. Thus, while no wealth tax will be leviable unless the net wealth exceeds Rs, 1 lakh in the case of individuals and Rs, 2 lakhs in the case of Hindu undivided families, once they are liable to tax, it will apply to their entire wealth. However, the exemptions in respect of approved financial investments, owner-occupied house and agricultural assets will continue
- 39. To tighten the incidence, the exemption from wealth tax currently available for household or personal jewellery and for shares forming part of initial capital issues is being withdrawn. In the case of conveyances, the exemption will now be limited to Rs. 25.000 in the aggregate. The existing provision in the Wealth Tax Act excluding from aggregation the assets transferred by an individual to the spouse or minor children is being done away with. A similar provision is being made in respect of conversion of assets of individuals into those of Hindu undivided families. While all these changes will not naturally yield any revenue this year, in future, the annual additional yield from these measures affecting wealth tax could be around Rs 14.5 crores. What is more important, they will impose a virtual ceiling on individual wealth at a much lower level than at present
- 40. As a further measure to discourage evasion of tax, conversion of the separate property of an individual into property belonging to a Hindu undivided family will be brought within the ambit of the gift tax.

### (b) Taxation of Companies

41. I am proposing several structural changes affecting the incidence of company taxation. While the rates of taxation on the ordinary income of companies are being maintained at existing levels, except for the rates on capital gains, the rate of surtax on company profits will be increased from 25 per cent to 30 per cent in the case of chargeable profits in excess of 15 per cent of the capital

- 42. The practice of offering a development rebate in respect of new investment has had, I feel, a full play. I am accordingly serving the required notice that no development rebate will be allowed on ships acquired or machinery or plant installed after May 31, 1974. Whatever the revenue implications of this step—and they are sizeable—will be fully revealed only after 1974-75, i.e., from the Fifth Plan onwards. But I shall consider myself amply rewarded if advance notice of this change quickens the pace of investment in the remaining years of the Fourth Plan.
- 43. At present, in the case of new industrial undertakings, ships and approved hotels, profits upto 6 per cent of the capital employed are entitled to tax exemption for a period of five years. Since debentures and long-term borrowings do not in any manner represent risk capital and interest thereon is in any case deducted, it was generosity on the part of the Government to extend the tax holiday provision even to such constituents of capital. I now propose that in calculating the limit of 6 per cent of the capital for purposes of tax-exemption, debentures and long-term borrowings will be excluded. This single measure will provide the exchequer with Rs. 10 crores during the current year; the yield for a full year will be of the order of Rs. 14 crores.
- 44. Priority industries currently enjoy a special tax exemption upto 8 per cent of their profits. I am proposing that the special exemption be reduced to 5 per cent of such profits. In addition, we have also decided to shorten the list of priority industries by excluding aluminium, motor trucks and buses, cement and refactories, soda ash, petro-chemicals and automobile ancillaries. The general economic conditions are now such that it is not necessary that these industries should continue to enjoy special benefits which were accruing to them hitherto. The two measures in relation to priority industries should yield Rs. 8 crores in future years; in 1971-72, the yield is likely to be about Rs. 6 crores.
- 45. The deduction of income upto Rs. 3,000 in the aggregate from investments in specified financial assets which was provided for last year will from now on be admissible only to individuals and Hindu undivided families
- 46. The concessional tax treatment of dividends received by foreign companies from a closely-held Indian company engaged in a priority industry will be discontinued: the foreign companies will be subjected to tax on such dividends at the usual rate of 24.5 per cent.
- 47 I am firmly of the view that the fiscal instrument must be deployed to discourage payment of high salaries and remunerations which no ill with the norms of egalitarian society. I accordingly propose to impose a ceiling on the remuneration of company employees which would be deductible in the computation of taxable profits. The ceiling is being set at Rs. 5,000 per month. Together with the existing ceiling of Rs. 1,000 per month in the case of perquisites, the allowable overall ceiling on remuneration and perquisites, for purposes of taxation, will be at Rs. 6,000 per month. In addition, I am proposing to reduce the tax deductible limits of daily allowance to employees while on tour.

### (c) Miscellaneous Concessions

- 48. Having already delivered the rough tidings, let me now detail some of the smoother ones. I propose to raise the standard deduction currently allowed for the computation of taxable income of employees who own a motor-cycle, a scooter or a moped from Rs. 60 to Rs. 75 per month; for others, who do not possess any of these, the standard deduction will be raised from Rs. 35 to Rs. 50 per month.
- 49. The quantum of deduction in respect of long-term savings through life insurance, provident fund contributions etc., is being substantially modified. At present, 60 per cent of the first Rs. 5,000 together with 50 per cent of the balance of such long-term savings are tax exempt. I am now proposing that for the first Rs. 1,000 of such savings, the quantum of deduction should be 100 per cent. On the next Rs. 4,000 of the qualifying savings, the proposed deduction will be 50 per cent, and on the balance 40 per cent. The limit for the savings qualifying for deduction will be raised from Rs. 15,000 to Rs. 20,000 in the case of individuals.
- 50 As a result of the changes in the standard deductions allowable for conveyance and long-term savings, an employee with an annual income of Rs. 6,600 will be exempt from income taxation provided he saves at least Rs. 400 in the approved form.

- 51. The tax concessions for promoting development and export of technical know-how and technical services, which have been available only to companies, will from now on also apply to individuals, Hindu undivided families and partnership firms. Certain further tax concessions are also at present available for expenditure on research and development. A Committee has recently been set up by the Government to review the position and make recommendations regarding further fiscal incentives that could be offered to encourage industrial research. The recommendations of the Committee will be given due weight.
- 52. The special deduction of income upto Rs. 3,000 from investments in specified financial assets available to individuals and Hindu undivided families would henceforth also cover interest on deposits with a cooperative society made by its members. Moreover, the interest paid by a cooperative society to its members on deposits made by them will be exempted from the requirement of deduction of tax at source. Shares of and member-deposits with a cooperative society will be regarded as approved investments which are exempt from wealth tax upto Rs. 15 lakhs. But I propor 1 to withdraw the exemption in respect of such investment in the case of descretionary trusts which are subject to taxation on their net wealth at the flat rate of 1.5 per cent, or at the rate applicable in the case of an individual whichevel is higher.
- 53. Three are certain minor concessions which I would now mention together. Coperative societies of workers or those engaged in fishing and allied activities will be exempted from tax on their entire business income. Local authorities deriving income from the supply of water or electricity to villages outside their jurisdiction will be exempted from tax on such incomes. A member of a cooperative housing society, to whom a building or a flat has been allotted under a house-building scheme of the society, will be regarded as the owner of that piece of property for purposes of wealth tax.
- 54. The Housing and Urban Development Finance Corporation will be exempted from tax on its income for a period of ten years; the tax-exempt status of the Deposit Insurance Corporation will be extended by a further period of five years
- 55. This brings me to the close of the various proposal relating to direct taxation. After taking into account the concessions, the net yield from the new direct tax measures from 1972-73 will be of the order of Rs. 57 crores. For 1971-72, however, the realisation is unlikely to exceed Rs. 27 crores.

### Indirect Taxation

56 I now turn to indirect taxes My proposals regarding customs duties belong broadly to two categories. The first set of proposals is aimed at rationallsing the rates structure of import duties. The other group of proposals is related to, and consequent on, the arrangements reached with a number of foreign countries who have agreed to release us from the bindings under the General Agreement on Tariffs and Trade in the matter of import levy on certain commodities

### (a) Import Duties

- 57. The existing rates structure of import duties, I confess, forms a complicated pattern. As of now, there are seven ad valorem rates of duty in force: 15 per cent. 27½ per cent, 35 per cent. 40 per cent, 50 per cent, 60 per cent and, finally, 100 per cent. In order to introduce an across-the-board simplification and to remove existing anomalies. I propose to have only four effective rates of import duty, namely, 30 per cent, 40 per cent, 60 per cent and 100 per cent.
- 58. I propose to bring in all items of machinery within the orbit of 30 per cent import levy. While this would imply a marginal increase of 2½ percentage points in the rate of duty in respect of project imports, the decrease of duty by 5 percentage points in respect of machinery in general would provide relief to smaller industrial units and units manufacturing equipment who import a part of the components and to all those who need to import small items of machinery by way of spares or balancing equipment. The equalisation of rates for all kinds of machinery would also simplify assessment and I hope, speed up assessment work. Items such as agricultural machinery and implements, dairy and poultry farming appliances would also now attract duty at the rate of 30 per cent instead of 15 per cent

- 59. Certain basic raw materials and non-ferrous metals will from now on be liable to duty at the uniform rate of 40 per cent. Iron and steel and unwrought copper will, however, attract the lower duty of 30 per cent.
- 60. It is proposed to eliminate the present rate of duty of 50 per cent and levy instead a higher rate of 60 per cent on most items. A similar upward revision has already been made in the course of the past two years with respect to the duty on chemicals, drugs, medicines, electrical and non-electrical appliances. What I am proposing now, therefore, is to bring all similar items together under the umbrella of the same rate of duty.
- 61. Till now, certain items used by the more affluent sections of the community, such as automobile components and dry fruits, were liable to a duty of 60 per cent instead of 100 per cent which is the standard rate for most imported consumer goods. This anomaly is now being removed. In addition, in view of the increase in the c.i.f. price as well as the high margin of profit, the specific rate applicable to cloves is being increased from Rs. 18 per kilogram to Rs. 60 per kilogram.
- 62. As a result of the release from the GATT bindings, we are now in a position to either impose a duty, or raise the existing rates of duty, on a number of items, including agricultural tractors, earth-shifting machinery, staple fibre excluding yarn, raw wool, unwrought copper, zinc and pig lead. I propose to avail of the opportunity. In view of the high margin of profit on imported staple fibre, I am proposing that the duty on it be fixed at 100 per cent. On unwrought zinc, pig lead and raw wool, the duty will be 40 per cent, and on copper, 30 per cent. Given the large disparity between the prices of imported and indigenous tractors, I have also decided on a levy of 30 per cent on imported agricultural tractors. The same rate of duty will apply on earth-shifting machinery.
- 63. Taking into account the effect of the rationalisation of import duties as well as the adjustments following from the release from the GATT bindings and the countervailing levies related to changes in excise duties to which I would soon turn, we should be able to get additional revenue to the extent of nearly Rs. 54 crores during the remaining part of the year.

### (a) Excise Duties

- 64. I now come to the proposals with respect to excise duties. Pursuant to the decision to continue the scheme of levying additional excise duties in lieu of sales tax on sugar, textiles and tobacco, we are committed to raise the over-all incidence of these additional duties to 10.8 per cent on the value of clearances by the end of the Fourth Plan period. Since this target has to be attained by 1973-74, it has become necessary to make a substantial beginning in the current year itself. For the present, I have decided to concentrate on cigarettes and, to some extent, on textiles.
- 65. There comes perhaps a time in the life of every smoker when the concern for his own health begins to outweigh the loyalty to an old and faithful companion. For those who cannot shake off their consuming passion, there is at least the consolation that the more to est they pay, the more they serve the common cause. I am, therefore, fortified in my decision to increase once again the taxation on cigarettes by the thought that whichever way my smoking friends react, there would be a net gain to national welfare. In place of the existing three slabs of duty on cigarettes. I propose to have five. By suitable adjustments of the basic and additional duties on these slabs, I hope to raise during the current year Rs. 33.20 crores of which Rs. 16 40 crores would go to the States by way of additional excise in lieu of sales tax. The effect of the proposals would be a marginal increase in the price of the cheaper varieties of cigarettes but a much sharper increase for the more expensive varieties.
- 66. Textiles, particularly coarse and medium varieties of cloth, are a basic necessity, and their price rose rather inordinately in 1970-71. Despite other constraints, I have therefore decided that the impost on textiles should be modest this year. I propose to step up slightly the additional excise duties on medium A and medium B varieties of cotton textiles from 4.8 paise to 6 paise per square metre and also to round off the additional duty leviable on coarse cloth from 3.6 paise to 4 paise per square metre. With respect to superfine and fine cloth, however, I propose to go much further, and raise the rates of the additional excise duty to 25 paise and 15 paise respectively per square metre. These several mea-

The second s Second second

sures should fetch an additional revenue of Rs. 4.90 crores which will accrue entirely to the States.

- 67. My other major proposal in regard to excises is in the area of motor spirit, solvents and a number of other minor lubricants. In view of the rise in international oil prices, there is need for the maximum economy in the utilisation of petroleum and petroleum products if we are to conserve our scarce foreign exchange resources. No doubt, there will be a certain hardship involved in this, but I am afraid it has to be borne by our people. To curb consumption, I, therefore, propose to increase the duty on motor spirit by Rs. 200 per kilo litre or 20 paise per litre. This measure will fetch an additional revenue of Rs. 36.30 crores in the current year.
- 68. There is extensive misuse of certain special boiling point spirits, otherwise known as solvent oils, as adulterants for motor spirit. To discourage this practice, I propose to raise the duty on solvents from the present rate of Rs. 45 per kilo litre to Rs. 845 per kilo litre. This measure will yield Rs. 4.25 crores during the current year.
- 69. Similarly, to prevent the adulteration of mineral turpentine oil with superior kerosene, an extra duty of Rs. 100 per metric tonne is being imposed on the former. In the case of liquid petroleum gas, I am proposing to abolish the ad valorem duty of 20 per cent and, instead, impose a specific duty of 25 paise per kilogram. The rate of duty which at present obtains on lubricating stock oils and greases directly derived from refined petroleum would also from now on apply to blended lubricating oils, greases and calcined petroleum coke. However, the base petroleum products used in the manufacture of the latter items would be given a credit for the duty that might already have been paid. I expect these measures to yield an additional revenue of Rs. 9 crores during 1971-72.
- 70. At present, carbon dioxide is liable to duty, but other gases, such as oxygen, chlorine, ammonia and refrigerant gases are exempt; these exemptions are being withdrawn. However, oxygen for medicinal use and ammonia used in the manufacture of fertilizers would continue to be exempted from duty. This measure is expected to yield Rs. 1.60 crores.
- 71. I also propose to raise the basic duty on glæssware to 20 per cent and on sheet and plate glass to 15 per cent. Glass shells, glass globes and laboratory glassware would be left untouched. While the duty on sanitary and glazed wares was revised last year, tableware and china ware left undisturbed. This deficiency I propose to make good this year; both these items will now attract a uniform duty of 20 per cent. These two changes are estimated to provide us this year with additional revenue of around Rs. 3.15 crores.
- 72. While air-conditioners pay a duty at the rate of 53.3 per cent till now, the evaporative type of coolers have been exempt from duty. This discrimination deserves to be removed. However, I am processing a duty of only 25 per cent on them and, at the same time, exempting them from the payment of the special excise duty. Vacuum flasks, similarly exempt till now, will also have to bear a levy of 15 per cent ad valorem. The gain to revenue would be Rs. 54 lakhs in the current year.
- 73. It is proposed to revise the duty on soap from the present effective rate of 11.4 per cent to 15 per cent. This would result in only a marginal increase in the price of toilet soaps. Household and laundry soaps are being left untouched. Because of partial exemption, the effective rate of duty on surface active agents works out to even less than that on ordinary household and laundry soaps. It is therefore proposed to abolish the partial exemption and restore the full statutory rate of duty on these products. These two revisions—relating to soap and surface active agents—are likely to yield a revenue of Rs. 2.55 crores for the rest of the year.
- 74. It is also proposed to tax certain other luxury items. Latex foam sponge, used extensively in the manufacture of foam mattresses, bears at present a relatively low basic rate of duty of 20 per cent ad valorem; I propose to double this rate of duty. A similar levy will be imposed on polyurethane foam as well as certain products made out of this particular foam. The basic rate of duty on plates, sheets and strips of rubber is also being stepped up from 20 per cent to 25 per cent ad valorem. These measures would bring in Rs 2.60 crores of additional revenue in 1971-72.

- 75. The duty on crown corks and pilter-proof caps is proposed to be ratsed from 1 paisa to 2 paise each. This measure is expected to yield Rs. 1.90 croies.
- 76. A few other changes are being proposed by way of rationalisation. These include an excise levy on dehydrated canned and bottled vegetables and on preparations of glucose and dextrose, the removal of the special concession of 50 paise per kg. on the basic excise duty for certain varieties of stiple hore, the rounding off of the duty on cement from 23.76 per cent to 24 per cent, levising the duty upwards on woollen yern and shifting a portion of the incidence to wool tops, revising the rates of duty on electric lighting bulbs other than those of 60 Watts and less, revising the rates for flourescent tubes as well as for electric fans and industrial fans other than those of a diameter not exceeding 16 inches, and removal of the concession of Rs. 500 per tonne on copper used in the manufacture of wires and cables. These assorted measures would yield a combined revenue of over Rs. 6 crores.
- 77. I have talked earlier about the need for the rapid reduction of income inequalities not only in the urban areas but also in the countryside. One way in which this could be brought about is through levying selectively indirect taxes on products and equipment used in agricultural operations by the richer sections of the peasantry. I propose, therefore, to tax agricultural tractors by charging a duty of 10 per cent ad valorem; this levy is likely to fetch a revenue of Rs. 3.40 crores in the current year.
- 78. To augment revenue, several new items are being introduced into the orbit of Central excise taxation. The commodities and the rates of duty are being so chosen that the net effect of these imposts on the price level will be negligible. The items I propose to bring in include perfumed hair oil, shampoos, lipsticks, pressure cookers, playing cards, zip fastners, photographic cameras, cinematographic projectors and linoleum. Very few of us perhaps would like to venture an opinion on the contribution made by perfumed hair oil, lipsticks or playing cards to the style, pace and quality of living in modern India. But Honourable Members will, I am sure, agree with me that most of these commodities constitute the appurtenances of high living; excise levies on them will have little effect on the level of living of the overwhelming mass of the community.
- 79. For the same reason, I am proposing a levy on certain ready-made garments which are mostly purchased by the well-to-do. However, in order to protect the small manufacturers, this levy will be confined to ready-made garments manufactured with the use of power and sold under registered trade marks or krand names. As a further concession to the small producers, clearances upto a specified value would be excluded from the excise provided the aggregate annual output in the unit concerned does not exceed a ceiling.
- 80. I also propose to introduce an excise levy on a number of producer goods such as ball and roller bearings, bolts, nuts and screws, electric insulation and non medical adhesive tapes, welding electrodes, grinding wheels and motor starters, as it is difficult to tax the end-products of these items and we are currently losing some potential revenue. The rate of duty will be 10 per cent. It is also proposed to charge a duty of 10 per cent on electric supply meters, typewrifer ribbons, mosaic tiles, fork lift and platform trucks and certain motor vehicle parts and accessories. Wherever necessary, the interests of the small producers will be protected by a concession similar to the one I have mentioned in the content of ready-made garments.
- 81. Four more themicals are loing added to the list of excisable chemicals and will be liable to duty as 10 per cent. A similar levy will also be imposed or camphor and menthol.
- $82.\ \mathrm{Thr}$  o thrious measures of new excise levies together are likely to yield Rs. 15 errors.
- 93. I now what to anothere an important new measure intended to meet the cost of the presence for children's health and natrition. I happened to serve a duty of 10 paise pe kg ron Maida processed by roller flour mills in the organised sector. The particular hour is usually consumed by the richer sections of the poweration and other iso used in the manufacture of sweets; the consumer to obread, another is an intermediate of maid lifely is used, is again the ly confined among the harden meaning the harden groups. I am such the slight additional expenditure which this lary would imply would be cheerfully borne by these consumers

since the resultant revenue of Rs. 7.4 crores which will accrue to the Centre will be earmarked for being spent or the welfare of children. In addition, the States also will receive nearly Rs. 1.8 croles from this measure.

- 64. I will now refer to a few encise concessions which I have considered desirable. To promote the use of the order of so in the manufacture of soap and thereby reduce our dependence on the refer tallow and oils. I propose to reduce the incidence of the duty on soap wherever there is certain minimum use of minor oils like neem and sal. The rate of duty on sodium silicate will be reduced to encourage the out put of cheaper varieties of soap in the small-scale sector. In order to toster the greater unitsation of cottonseed oil, the existing excise rebate for using this oil in the manufacture of vanaspati will be increased. A similar concession is also proposed to be accorded to rice-bran oil.
- 85. With a view to providing some relief to the small and marginal units using powerlooms for manufacturing cotion fabrics, I propose to reduce the rate of compounded levy on units where not more than 4 powerlooms are installed from Rs. 50 to Rs. 10 per loom per annum. In the case of units employing more than 4 powerlooms, the compounded levy will be half of the existing rates. The concession at present available to independent processors, will be rationalised. There are also a couple of marginal concessions for the manufacturers of embroidery and leather cloth.
- 86 All these reliefs and concessions together would cost the exchequer around Rs. 1.50 crores for the remaining part of the year.
- 87. This brings me to the end of the rather long enumeration of the proposed changes with regard to excise duties. Taking all the proposals for excise duties together, the total yield for the rest of the current financial year will be roughly Rs. 89 crores for the Centre and Rs. 43 crores for the States.

### (c) Other Measures

- 88. I am afraid, having dealt with direct taxes, customs and excises, I am not quite through as I have yet to propose to the Honourable Members a new measure which is not quite in the nature of an excise levy. This is a tax which I propose to impose on foreign travel. The levy will be at the rate of 20 per cent ad valorem on all tickets purchased in rupees; tickets paid for in foreign exchange will be exempt. The only other major exemption would be for students and scientists. The estimated revenue from this measu e which would come into effect from a date to be notified later, wou'd be about Rs. 7.0 crores. In case any Honourable Member feels that I am taking away what many airlines have graciously offered by way of concessional fares, I wish to assure them that with the proposed ad valorem tax, the value of the concession in absolute terms would in fact be enhanced.
- 89. And now I come to the final set of proposals I have to announce on behalf of my colleague, the Minister for Communications. Honourable Members are aware that Posts and Telegraph branches have incurred heavy losses in the past and are anticipated to show a loss of as much as Rs. 15 crores during the current year. Both the Tariff Inqury Committee which was set up to examine the rates structure of the Posts and Telegraphs Department and the Administrative Reforms Commission have recommended the need for financial viability and the desirability of surplus being generated from the operation of Posts and Telegraphs. A certain upward revision in tariffs is therefore inescapable. While proposing this revision, we have kept in view the problems faced by the less effluent sections of society; items like postcards letter cards, and eletters have thus been kept completely out of the purview of the upward adjustment of rates. Most of the proposed increases relate to registration fees for and articles, and telegraph and telephone tariffs. The registration and packet lees are printed by 5 page and 10 paise respectively for 410 grains. The care are also minor adjustments in the charges for telegrapes consisted and one of the particles are also minor adjustments in the charges for telegrapes consisted and telegraphs. The care are also minor adjustments in the charges for telegrapes consisted and telegraphs. The latest are also minor adjustments in the proposed changes is bong care dated also given the proposed changes is bong care dated also given the proposed changes is bong care dated also given the proposed changes is bong care dated also given the proposed changes is bong care dated also given the proposed changes is bong care dated also given the proposed changes is bong care dated also given the proposed changes is bong care dated also given the proposed changes is bong care dated also given the proposed changes is bong care dated.
- 90. So for as the Union is the scencerned, the various proposals outlined would imply, for 1971-72, a difference revenue aggregating to Rs. 177 crores. The budgetary gap of Rs. 397 and a had indicated earlier will accordingly be now scaled down to Rs. 220 crores

- 91. I have now come to the end of my labours. Quite candidly, it has been for me a difficult Budget to frame. There are a wide range of fiscal proposals and, in some directions, the impact of the new levies cannot but be considerable. Let me remind Honourable Members, however, that the price rise in the economy has been sufficiently disquieting last year, and the budgetary deficit must therefore be kept within reasonable limits. In addition to the obligation that we owe to the community to increase substantially the size of the Plan and to provide for greater employment opportunities, there is, at this stage, still the imponderable factor of the developments in East Bengal and the rising flood of evacuees.
- 92. Fiscal policy, however, is not a matter simply, or even primarily of raising resources to meet the inescapable demands on the national exchequer. It must serve larger objectives as well and guide the economy in desired directions. It must, in particular, make a significant impact on existing inequalities in income, wealth and economic power and reduce ostentatious consumption. It is for this reason that, in the field of direct taxation, I have introduced a number of measures whose significance to revenue in the short run may not be so great but which are vital for the achievement of a just society. In the field of indirect taxation also, objectives such as those of reducing pressures on our balance of payments have been kept in mind; and care has been taken to ensure that only a small proportion of the additional burden is borne by the common man.
- 93. It is hardly possible to claim that a new social and economic orders can be ushered in through budgetary policy alone, much less through a single Budget. In a Budget of this magnitude it is also difficult to reconcile all the objectives we have set before ourselves. But I hope I have not flinched from the duty of trying to meet the immediate and urgent requirements while furthering our accepted objective of a truly socialist society.